छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 189 ■ अम्बिकापुर, मंगलवार 21 जुलाई 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

‘खोया फोन मिला तो आंखें भर आई, कहा-धन्यवाद सरगुजा पुलिस’

पुलिस ने 31 लाख का सामान नहीं, 129 लोगों का भरोसा वापस लौटाया

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के दिशा-निर्देशन में साइबर सेल अंबिकापुर और जिले की समस्त थाना/चौकी पुलिस टीम ने गुम मोबाइलों की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत पिछले 5 महीने में कुल 129 नग गुम मोबाइल बरामद कर उनके असल मालिकों को वापस सौंपे गए। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 31 लाख रुपये है। उपस्थित लोगों ने पुलिस टीम की तकनीकी दक्षता, समन्वय और सतत प्रयासों की प्रशंसा की।

पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा मोबाइल धारकों को मोबाइल के साथ उनकी खुशियां लौटाई गईं। मोबाइल पाकर जहां एक वृद्ध महिला के चेहरे में मुस्कान उभर आई, वहीं ग्रामीण अन्य लोगों की खत्म हो चुकी उम्मीद मोबाइल के साथ वापस मिली।

इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल धारकों को साइबर अपराधियों से बचने के लिये टिप्स बताए, ताकि वे जाने-अनजाने में ऐसे अपराधियों के चंगुल में आने से बच सकें, और त्वरित पुलिस के संज्ञान में ऐसे मामलों को लाएं। कार्यक्रम में एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो, एसडीओपी ग्रामीण तुल सिंह पट्टावी, रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत, थाना प्रभारी कोतवाली शशिकान्त सिन्हा, गांधीनगर प्रवीण कुमार द्विवेदी, साइबर सेल प्रभारी एएसआई अजीत मिश्रा, आरक्षक अनुज जायसवाल, अमित विश्वकर्मा, रिंकू गुप्ता, अशोक यादव, अमित विश्वकर्मा, वीरेंद्र पैकरा, उमाशंकर साहू, रमेश राजवाड़े, राहुल केरकेट्टा सहित पुलिस टीम मौजूद रही।

तकनीकी माध्यमों से किया मोबाइल ट्रैक

बता दें कि, जिले के विभिन्न थाना, चौकी में गुम मोबाइल की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो और नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के नेतृत्व में साइबर सेल ने सर्विलांस और तकनीकी माध्यमों से मोबाइल ट्रैक किया। अधिकतर मामले बाजार, सब्जी मंडी, चौक-चौराहे, यात्रा और मंदिरों के आसपास से सामने आए थे। नागरिकों ने थाना, चौकी और भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस गुम मोबाइल की खोजबीन को लेकर वैधानिक जांच, कार्रवाई में निरंतर लगी थी। सरगुजा पुलिस ने फरवरी 2026 में भी 525 नग गुम मोबाइल बरामद कर वास्तविक मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया था।

साइबर जागरूकता और पोलिस की-वर्ड

कार्यक्रम में डीआईजी राजेश कुमार अग्रवाल ने नागरिकों को साइबर ठगी से बचाव के तरीके बताए और पोलिस की-वर्ड की जानकारी दी। उन्होंने पोलिस के एक-एक इंग्लिश लेटर को परिभाषित करते हुये बताया कि ‘पी-पासवर्ड’ पासवर्ड मजबूत और गोपनीय रखें, किसी से साझा न करें। ‘ओ-ओटीपी’ कभी भी ओटीपी बैंक, पुलिस या रिश्तेदार के नाम पर मांगने पर भी न बताएं। ‘एल-लिंक’ अनजान ईमेल/एसएमएस के लिंक पर क्लिक न करें। ‘आई-आइडेंटिफिकेशन’ आधार, पैन, वोटर आईडी की फोटो सोशल मीडिया पर न डालें, दुकान में मूल कॉपी न छोड़ें। ‘सी-केयरफुल’ व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें, लालच में न आएं, बैंकिंग काम स्वयं बैंक जाकर करें। ‘ई-इमरजेंसी’ साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या नजदीकी पुलिस स्टेशन/साइबर सेल से संपर्क करें। ‘रुको, सोचो और कार्रवाई करो’ का स्लोगन अपनाएं।

पुलिस टीम के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने मोबाइल धारकों को संबोधित करते हुए कहा कि कई मोबाइल धारकों को मोबाइल गुमने के पश्चात वापस मिलने की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन पुलिस टीम के सामूहिक प्रयास से गुम मोबाइल खोजकर वापस दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा मोबाइल धारक अपने मोबाइल को संभाल कर रखें, स्वयं सचेत रहें एवं दूसरों को भी सचेत करें। मोबाइल में हर किसी की कई गोपनीय एवं महत्वपूर्ण जानकारी रहती है। मोबाइल गुमने पर इन जानकारियों का गलत एवं मनमाना तरीके से उपयोग कर साइबर ठगी जैसी घटनायें कारित की जाती हैं। उन्होंने मोबाइल वापस पाने वाले धारको को शुभकामनायें दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसा अभियान चलाकर गुम मोबाइल असल मालिकों को सौंपे जाएंगे।

राहवीर योजना और अवैध प्रवासी टोल फ्री नंबर

इस दौरान राहवीर योजना की जानकारी देते हुये एसएसपी ने बताया कि, दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को शासन के द्वारा 1 महीने के अंदर 25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अवैध प्रवासियों की सूचना के लिए टोल फ्री नंबर 18002331905 और सरगुजा पुलिस हेल्पलाइन 9479193599 या डॉयल 112 पर सूचना देने की अपील की गई। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

‘दिल्ली में ट्राइबल एक्सप्रेस की दौड़’

अमरजीत, कवासी सहित कई दिल्ली में

छ.ग.फ्रंटलाइन रायपुर। नई दिल्ली में बस्तर सरगुजा और मध्य छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के आदिवासी चेहरों की मौजूदगी ने प्रदेश में चर्चाओं को हवा दे दी है। यह जमावड़ा ऐसे वक्त हुआ है जबकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर सिंहदेव का नाम चर्चा में है। हालांकि इन नेताओं ने अपनी मौजूदगी को व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से होना बताया है।

बता दें कि, कांग्रेस के क़द्दावर आदिवासी नेता अमरजीत भगत इस आदिवासी एक्सप्रेस के प्रमुख चेहरे के तौर पर दिल्ली में मौजूद हैं। उनके साथ बस्तर के धरती पकड़ नेता और कोंटा विधायक कवासी लखमा भी हैं। इस ट्राइबल एक्सप्रेस में एक डब्बा जनक ध्रुव के नाम का भी है जो बिंद्रा नवागढ़ से विधायक हैं, और आदिवासी समाज के लोकप्रिय चेहरे हैं। अपुष्ट खबरें हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुछ अन्य प्रभावशाली आदिवासी चेहरे भी दिल्ली में मौजूद हैं। इनमें संगठन से जुड़े नाम भी शामिल हैं,जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं। एक साथ कद्दावर आदिवासी वर्ग के इन चर्चित चेहरों की अपेक्षा से ज्यादा मौजूदगी ने यह सुविधा दी है कि यह लिखा जा सके ‘दिल्ली में ट्राइबल एक्सप्रेस दौड़ रही है।’

महिला नेत्रियों की भी मौज़ूदगी

नई दिल्ली में इस समय छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की नेत्रियां भी मौजूद हैं। इनमें छन्नी साहू, ममता चंद्राकर, सविता साहू, आरती महोबिया, वंदना नाग सहित कई नाम शामिल हैं। हालांकि महिला कांग्रेस की इन नेत्रियों की मौजूदगी के पीछे वजह ‘घेराव कार्यक्रम’ बताया गया है। इन महिला नेत्रियों की ओर से यह बताया गया है कि 543 सीट पर महिला आरक्षण के मसले पर संसद घेराव के कार्यक्रम के लिए वे सभी दिल्ली पहुंची हैं। यहां यह भी याद रखा जाना चाहिए कि, प्रदेश महिला कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष पद को लेकर गाहे-बगाहे हलचल होती है। इस समय संगीता सिन्हा महिला कांग्रेस की प्रभारी अध्यक्ष हैं।

भूपेश आज पहुंचेंगे दिल्ली-कांग्रेस के महासचिव और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के कार्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार पाटन विधायक भूपेश बघेल कल देर शाम दिल्ली पहुंचना होगा।

जमीन विवाद में शिक्षक की चाकू-हथौड़े से हत्या, दो चचेरे भाई गिरफ्तार

आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों के घर में लगाई आग

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राधानगर में सोमवार की सुबह एक शिक्षक की नृशंस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुराने जमीन विवाद की रंजिश में शिक्षक जयकरन जगते की चाकू और हथौड़े से हमला करके हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में मृतक के दो चचेरे भाइयों बृजमोहन (25 वर्ष) और हरिमोहन (24 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई। आक्रोशित स्वजन ने आरोपियों के घर में आग लगा दी, जिसे पुलिस ने तत्काल पहुंचकर बुझा दिया।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार की सुबह करीब 9.30 बजे शिक्षक जयकरन जगते अपने घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर स्थित स्कूल जाने के लिए बाइक से निकले थे। रास्ते में सड़क किनारे मवेशियों के बैठने वाले स्थान के पास पहले से घात लगाए बैठे दोनों आरोपियों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। आरोपियों ने चाकू और हथौड़े से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे जयकरन जगते गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े। गर्दन पर गंभीर चोट लगने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जमीन का बंटवारा होने के बाद भी मृतक उन्हें जमीन जोतने और सीमांकन नहीं करने दे रहा था और लगातार परेशान कर रहा था। इसी रंजिश के चलते उन्होंने वारदात को अंजाम दिया।

घटना की सूचना मिलते ही त्रिकुंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर ली। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या की खबर फैलते ही मृतक के स्वजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। एहतियात के तौर पर गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

> मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस आगे की विवेचना कर रही है। दोनों आरोपी चचेरे भाई हैं।
>
> **विश्व दीपक त्रिपाठी, एएसपी बलरामपुर**

भाजपा नेताओं से जुड़े मामलों में हुई कार्रवाई से अवगत होने आईजी से मिले कांग्रेसी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में सरगुजा रेंज आईजी दीपक झा से मिला। प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। इनके द्वारा भाजपा नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार, मारपीट और जमीन घोटाले जैसे गंभीर मामलों में कांग्रेस के द्वारा दिये गये ज्ञापन पर पुलिस कार्रवाई की जानकारी ली गई।

उल्लेखनीय है कि विगत माह कलाकेंद्र मैदान के आबंटन में रिश्वतखोरी से संबंधित एक मोबाइल वार्ता का ऑडियो वायरल हुआ था। मैदान के आबंटन के लिए लेनदेन की इस वार्तालाप में मौजूद स्वर अंबिकापुर महापौर और भाजपा जिलाध्यक्ष का बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीतापुर में विधायक के द्वारा राजस्व अधिकारी से मारपीट, भिट्ठी कला में एक बेवा महिला के साथ जमीन खरीद में धोखाधड़ी के मामले में भाजपा के बड़े नेता या इनके समर्थकों का शामिल होना सामने आया है। कांग्रेस ने इन घटनाओं के सामने आने के बाद थाने से लेकर उच्च पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई हेतु ज्ञापन सौंपा, लेकिन पुलिस का रवैया अब तक शिथिल और निराशाजनक रहा है। 6 जुलाई को कांग्रेस ने न्याय रैली निकाल सरगुजा रेंज के आईजी को कार्रवाई हेतु लिखित निवेदन, साक्ष्य के साथ दिया, 2 सप्ताह बीतने के बावजूद इन मामलों में ठोस कार्रवाई की जानकारी नहीं मिलने पर सोमवार को पुनः कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सरगुजा रेंज के आईजी से मुलाकात कर कार्रवाई की जानकारी मांगा।

आईजी ने कहा-अब नतीजे सामने आएंगे

सीधी चर्चा में आईजी ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को हो रही कार्रवाई की जानकारी देने के साथ ही आश्वस्त किया है कि इन मामलों को लेकर अब नतीजे सामने आएंगे, उन्हें दुबारा इन मांगों के लिए नहीं आना पड़ेगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि कार्रवाई संतोषजनक होनी चाहिये अन्यथा कांग्रेस, भाजपा मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दौरे में विरोधस्वरूप काला झंडा लेकर खड़ी मिलेगी। प्रतिनिधिमंडल में संजय विश्वकर्मा, विनीत विशाल जायसवाल, पापिन्दर सिंह, शुभम जायसवाल मौजूद रहे।

कलेक्टर दर पर मिले मानदेय, 2000 रुपये मिलने से नाराज रसोइया

मांग पूरी नहीं होने पर 2 दिन हड़ताल फिर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा जिले के स्कूलों की रसोइयों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कम मानदेय और आर्थिक परेशानियों से नाराज रसोइयों ने आगामी दिनों में हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल के पूर्व रसोइया संघ ने सरगुजा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। मैनपाट ब्लॉक की रसोइयों ने कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन में कहा है कि उन्हें प्रतिमाह केवल 2000 रुपये मानदेय मिलता है, जबकि वे सुबह से दोपहर तक स्कूलों में भोजन बनाना, बच्चों को भोजन परोसना, बर्तन साफ करना और अन्य काम करती हैं। रसोइयों का कहना है कि इतने कम मानदेय में घर का खर्च चलाना और बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से कलेक्टर दर के अनुसार पूर्णकालिक वेतन देने की मांग की है। अगर मांग नहीं मानी गई तो रसोईया संघ 2 दिवसीय हड़ताल करके शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराएगा। संघ का कहना है कि इसके बाद भी समाधान नहीं निकला तो आंदोलन तेज किया जाएगा और सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग रसोइयों की मांगों पर क्या फैसला लेता है और प्रस्तावित हड़ताल से पहले कोई रास्ता निकलता है या नहीं।

श्रीमती ललिता दोहरे, रसोईया का कहना है कि सुबह 7 बजे से स्कूल जाते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को परोसते हैं, बर्तन धोते हैं। 2000 रुपये में गैस, तेल, बच्चों की जरूरतें पूरी कर पाना असंभव है। इन्होंने कलेक्टर दर के हिसाब से वेतन देने पर जोर दिया। सीता एक्का ने कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो हम 2 दिन स्कूल का चूल्हा बंद कर देंगे। अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो हम सब मिलकर इस्तीफा दे देंगे। सरोज सोनवानी का कहना है कि इतनी मेहनत के बाद मिलने वाले 2000 रुपये किसी काम के नहीं हैं। सरकार को उनकी मांगों को पूरा करने के लिये कदम बढ़ाना चाहिए। वे सुबह से दोपहर तक भोजन बनाने, बच्चों को परोसने के साथ ही बर्तन साफ करने सहित अन्य काम में पूरी तन्मयता के साथ अपना समय देती हैं।

1.92 करोड़ का केसीसी ऋण घोटाला, कम्प्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार

छ.ग.फ्रंटलाइन सीतापुर। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा पेटला में 127 किसानों का फर्जी हस्ताक्षर करके 1 करोड़ 92 लाख 82 हजार 96 रुपये की केसीसी ऋण अनियमितता के मामले में सीतापुर थाना पुलिस ने कम्प्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। जांच में तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक भुपेन्द्र सिंह, सहायक लेखापाल शिवशंकर सोनी, कैशियर ललिता सिन्हा, सामान्य सहायक सुमित कुमार, दैनिक वेतनभोगी कम्प्यूटर ऑपरेटर दीपक कुमार चक्रधारी, तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी मदन सिंह, प्राधिकृत अधिकारी जोगी राम, सैनाथ केरकेट्टा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं तत्कालीन समिति प्रबंधक सहित अन्य को संयुक्त रूप से दोषी पाया गया था। मामले में धारा 318, 316(5), 61(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज है। विवेचना के दौरान दीपक कुमार चक्रधारी पिता मनोहर राम, 29 वर्ष, निवासी अखोराकला थाना जयनगर जिला सूरजपुर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ की, उसने अन्य आरोपियों के साथ सांठगांठ कर अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। अन्य आरोपी अभी फरार हैं। कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, एएसआई डेविड मिंज, प्रधान आरक्षक नंदकुमार प्रजापति, तिजलाल पैकरा, आरक्षक महेन्द्र नाग शामिल रहे।

सभी पात्र हितग्राहियों का सत्यापन शत-प्रतिशत प्राथमिकता से पूर्ण करें : कलेक्टर

★ समय-सीमा की बैठक संपन्न ★ पेंशन की निरंतरता के लिए समय पर सत्यापन जरूरी
★ राजस्व, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की गहन समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सेवा सेतु से जुड़ी प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों, अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को फील्ड स्तर पर नियमित समीक्षा कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति लाकर जिले की रैंकिंग बेहतर बनाए। कलेक्टर ने पीजी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी लेते हुए सभी विभागों को शिकायतों एवं आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पीएम जनमन आवास की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्वीकृत आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्पेशल प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे आवासों पर विशेष फोकस करते हुए कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने पीएम जनमन योजना अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों एवं केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत पहाड़ी कोरवा समुदाय के लिए स्वीकृत आवासों की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से टीबी स्क्रीनिंग, नियमित टीकाकरण तथा यू-विन पोर्टल में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आरबीएसके के माध्यम से स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अधिक से अधिक बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड निर्माण की समीक्षा करते हुए ग्रामीण एवं नगरीय निकायों के समन्वय से कार्ययोजना बनाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही वय वंदन कार्ड निर्माण में भी बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने को कहा।

सामाजिक सहायता पेंशन हितग्राहियों के आधार आधारित सत्यापन एवं एनएसएपी पोर्टल पर अपलोड की साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी हितग्राहियों का सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश दिए। ताकि सत्यापन हेतु शेष हितग्राहियों को सत्यापन के अभाव में पेंशन लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसलिए सभी पात्र हितग्राहियों का सत्यापन पात्र के आधार पर पूर्ण कराएं।

कलेक्टर ने नान एवं एफसीआई में चावल जमा करने की स्थिति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों में भंडारण एवं वितरण की समीक्षा करते हुए समय से हितग्राहियों का राशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद एवं बीज की उपलब्धता तथा वितरण की जानकारी लेते हुए किसानों को समय पर उपलब्ध कराने को कहा ताकि किसनों को किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने एग्रीस्टैक पंजीयन की समीक्षा कर अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने शिक्षा मद अंतर्गत 2024-25 में स्वीकृत लघु निर्माण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने स्वीकृत नवीन शौचालय निर्माण एवं शौचालय मरम्मत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र शिविरों की समीक्षा करते हुए विद्यालयों के सभी पात्र विद्यार्थियों के प्रमाण-पत्र समय पर बनाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने विद्यालय परिसरों में पोषण वाटिका विकसित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें ऐसी सब्जियां एवं पौधे लगाए जाएं, जिनका उपयोग मध्यान्ह भोजन में किया जा सके और बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध हो सके। इस दौरान कलेक्टर ने पोषण पुनर्वास केंद्र संचालन की जानकारी लेते हुए बेहतर संचालन के निर्देश दिए। सेंटर में भर्ती किए गए बच्चों की संख्यात्मक जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि कुपोषित एवं जरूरतमंद बच्चों को चिन्हित कर समय पर एनआरसी में भर्ती कराने तथा उपचार एवं नियमित फालोअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने जिले के बसाहटों में स्थापित हैंडपंप की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जल जीवन मिशन की जलवर्धन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर श्री आर. एस. लाल, श्री चेतन बोरघरिया, श्री आर.एन. पाण्डेय, सहित सभी अधिकारीगण उपस्थित थे।

रात में चौकीदार की तबीयत बिगड़ी, स्कूल में लाखों की चोरी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एनएच 43 किनारे स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजबनगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सामान चोरी कर लिए हैं। चोरी की सूचना पर जयनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। घटना स्थल पर डॉग स्क्वायड की मदद लेने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग सकी है। स्कूल की प्राचार्य द्वारा जयनगर थाना में दिए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि 19 जुलाई की रात विद्यालय में ड्यूटी पर तैनात रात्रिकालीन चौकीदार मुखल राम यादव की रात करीब 10 बजे अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण वह अपने घर चला गया था। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने विद्यालय परिसर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।

चोरों द्वारा विद्यालय के कंप्यूटर कक्ष एवं अन्य कमरों का ताला तोड़कर एसर कंपनी का 1 मॉनिटर, 1 सीपीयू, 1 की-बोर्ड, 1 माउस, फेयर इंडिया कंपनी का 1 सीलिंग फैन, अहूजा कंपनी के लगभग 3 फीट ऊंचाई वाले 2 साउंड बॉक्स, रॉकलाइट कंपनी का रिचार्जेबल वायरलेस कराओके स्पीकर सिस्टम, जिसमें 2 वायरलेस माइक्रोफोन भी शामिल थे, जो चोरी कर ले गए हैं।विद्यालय प्रबंधन के अनुसार चोरी हुए उपकरण शैक्षणिक गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा विभिन्न सरकारी आयोजनों में उपयोग किए जाते थे। चोरी गए सामानों की कीमत करीब दो लाख रुपए आंकी जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि विद्यालयों में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और नियमित निगरानी होती, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। रात में चौकीदार के जाने के बाद विद्यालय पूरी तरह असुरक्षित हो गया, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। प्राचार्य की लिखित सूचना पर जयनगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है।मामले में संभावित संदिग्धों की तलाश की जा रही है।

डॉग स्क्वायड का नहीं मिला सहयोग

बताया जा रहा है कि विद्यालय में चोरी की घटना उपरांत पुलिस टीम ने डॉग स्क्वायड की भी मदद लिया, लेकिन आशातीत सहयोग नहीं मिल सका। डॉग द्वारा कोई बेहतर परिणाम नहीं मिलने उपरांत पुलिस अब अपने स्तर से अज्ञात आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है।

कलेक्टर के निर्देशन में बाल सुरक्षा पर विशेष जागरूकता अभियान

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिले के बच्चों और किशोर-किशोरियों को सुरक्षित, जागरूक बनाने के उद्देश्य से लगातार जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहा है। इसी कड़ी में आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम लोधा एवं शासकीय उच्चतर कन्या विद्यालय कछिया में बाल संरक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, गुड टच-बैड टच, बाल सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, नशामुक्ति, बाल विवाह, बाल श्रम, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को बताया कि उनका सुरक्षित बचपन उनका अधिकार है। यदि कभी वे किसी असहज या शोषण की स्थिति का सामना करें तो बिना झिझक अपने माता-पिता, शिक्षकों, या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से सहायता लें।

इस दौरान बच्चों को गुड टच बैड टच की पहचान की जानकारी दी गई और सही समय पर बिना झिझक के जानकारी देने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, बाल विवाह के बारे में जानकारी दी गई ।

संवेदनशीलता के साथ करें आवेदनों का समाधान : कलेक्टर

जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने समय-सीमा की बैठक पश्चात आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आम नागरिकों की समस्याएं एवं मांगें गंभीरतापूर्वक सुनीं। जनदर्शन में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी मांग, समस्यायें एवं शिकायत से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदन का गंभीरतापूर्वक परीक्षण करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनदर्शन शासन और आम जनता के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम है तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति की समस्या का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ समाधान करें। ताकि आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित कर इसकी जानकारी आवेदको को भी उपलब्ध कराएं।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने बैठक

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल, गरिमामय एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर समारोह की सभी व्यवस्थाओं को समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने तथा विभागवार जिम्मेदारियां तय कर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

समयबद्ध एवं गरिमामय आयोजन के दिए निर्देश

कलेक्टर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय गौरव का पर्व है, इसलिए समारोह की प्रत्येक व्यवस्था व्यवस्थित, अनुशासित एवं गरिमापूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने परेड, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण, बैठक व्यवस्था, पेयजल, विद्युत, साफ-सफाई, चिकित्सा सुविधा, यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्मान, शासकीय भवनों पर रोशनी की व्यवस्था, स्कूली विद्यार्थियों की सहभागिता तथा राष्ट्रीय ध्वज संहिता का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय-सीमा में तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर आर. एस. लाल, चेतन बोरघरिया, श्री आर.एन. पाण्डेय, सहित सभी अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित के लिए किया गया किट वितरण

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जल जीवन मिशन अंतर्गत वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में जल परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा हैं।

इसी कड़ी में विकासखंड कुसमी की ग्राम पंचायत नीलकंठपुर में जल परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण उद्घोष के माध्यम से ग्रामीणों की जल बहनों को फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में पेयजल की गुणवत्ता की जांच करने की प्रक्रिया, जल स्रोतों के संरक्षण तथा जल जीवन मिशन की विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसी प्रकार विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम रामपुर में भी जल बहनों को फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जल के नमूनों की जांच की विधि का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया तथा नियमित रूप से जल गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए प्रेरित किया गया। विकासखंड कुसमी के ग्राम स्याही में एफटीके प्रशिक्षण एवं वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जल बहनों को फील्ड टेस्ट किट के उपयोग का प्रशिक्षण देने के साथ ही फील्ड टेस्ट किट का वितरण भी किया गया, ताकि वे अपने ग्राम में पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच कर सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

जल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाते हुए स्थानीय स्तर पर पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच सुनिश्चित करना तथा सुरक्षित पेयजल के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना है।

रेलवे प्रबंधन ने तीन दर्जन से अधिक कब्जाधारियों को थमाया नोटिस

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिश्रामपुर-करंजी रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे प्रशासन ने नगर पंचायत बिश्रामपुर के वार्ड क्रमांक 15 स्थित झुग्गी बस्ती क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर कच्चे-पक्के मकान बनाकर रह रहे तीन दर्जन से अधिक कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलपथ बैकुंठपुर द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं हटाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार संबंधित भूमि रेलवे की संपत्ति है, जिस पर वर्षों से अवैध रूप से कब्जा कर मकान और अन्य निर्माण कर लिए गए हैं। ज्ञात हो कि नगर पंचायत बिश्रामपुर अंतर्गत जेएमक्यू कॉलोनी के पीछे स्थित रेलवे और एसईसीएल की खाली पड़ी भूमि पर कई लोगों ने स्थायी और अस्थायी आवास बना लिए हैं। अंबिकापुर-अनूपपुर रेल लाइन के दोनों ओर बड़ी संख्या में मकान बनने से सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं।

रेल पटरी से सटे निर्माण के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। लोगों के घरों से निकलने वाले खाद्य अवशेष और कचरे के कारण मवेशी अक्सर रेल पटरी तक पहुंच जाते हैं, जिससे कई बार ट्रेन की चपेट में आकर उनकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा रेलवे द्वारा पूर्व में प्रस्तावित सुरक्षा दीवार का निर्माण भी अतिक्रमण के चलते शुरू नहीं हो सका था। रेलवे प्रबंधन अब सुरक्षा और भविष्य की विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त रुख अपनाए हुए है।

वहीं नोटिस जारी होने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने रेलवे अधिकारियों से बरसात का मौसम समाप्त होने तक कार्रवाई स्थगित रखने और प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त समय देने की मांग की है।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता:उप मुख्यमंत्री शर्मा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर।उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जिले के आठ स्वास्थ्य संस्थानों को कवर्धा में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणपत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संस्थानों की बेहतर कार्यप्रणाली और मरीजों के प्रति संवेदनशील सेवाओं का प्रमाण है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पलानसरी, मिनमिनिया, गोछिया, वीरेंद्रनगर, गौरमाटी, धरमगढ़, गेंदपुर एवं रंजीतपुर को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणपत्र प्रदान किए। कबीरधाम जिले की 60 शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणपत्र प्राप्त कर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।यह प्रमाणपत्र स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध उत्कृष्ट गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं एवं रोगी-केंद्रित देखभाल का प्रमाण है। यह उन संस्थानों को प्रदान किया जाता है, जो सेवा प्रावधान, रोगी अधिकार, समर्थन सेवाएं, नैदानिक सेवाएं, संक्रमण नियंत्रण तथा गुणवत्ता प्रबंधन जैसे कठोर मानकों पर खरे उतरते हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार व्यापक तैयारी करनी होती है। इसके बाद जिला एवं राज्य स्तरीय टीम संस्था का निरीक्षण कर दस्तावेजों का परीक्षण, साक्षात्कार, साफ-सफाई, आवश्यक दवाइयों एवं जांच किट की उपलब्धता, भवन की स्थिति, जल एवं विद्युत आपूर्ति तथा मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करती है। प्रत्येक मानक में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने के बाद ही संस्था राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणीकरण हेतु सक्षम पोर्टल पर आवेदन करती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य शासन द्वारा जिले के 73 स्वास्थ्य संस्थानों को प्रमाणीकरण हेतु तैयार करने का लक्ष्य दिया गया था। इसके विरुद्ध कबीरधाम जिले ने 91 शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों (125 प्रतिशत) में गुणवत्ता सुधार का कार्य प्रारंभ कर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।इन 91 स्वास्थ्य संस्थानों में से 60 संस्थानों का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणीकरण पूर्ण हो चुका है, जबकि 12 संस्थानों के परिणाम लंबित हैं तथा 19 संस्थानों में तैयारी जारी है।इनमें जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया, एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 52 उप स्वास्थ्य केंद्रों का प्रमाणीकरण पूर्ण हो चुका है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक से प्रमाणित होने के बाद उप स्वास्थ्य केंद्रों को 2.16 लाख रुपये, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 3 लाख रुपये, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय को प्रति बेड 10 हजार रुपये की दर से प्रतिवर्ष तीन वर्षों तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

नेटबॉल प्रतियोगिता में जांजगीर-चांपा ने दुर्ग को हराकर जीता राज्य स्तरीय खिताब

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर।राजधानी के सप्रे मैदान एवं डिग्री गर्ल्स कॉलेज मैदान में आयोजित 'प्रथम छत्तीसगढ़ सीनियर राज्य स्तरीय मिक्स नेटबॉल प्रतियोगिता' का रंगारंग समापन हुआ। इस रोमांचक टूर्नामेंट में जांजगीर-चांपा की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में दुर्ग की मजबूत टीम को 25-21 के स्कोर से हराकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। वहीं, राजनांदगांव और गरियाबंद की टीमें संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहीं। समापन समारोह छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अकरम खान के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि में सैयद राजा, उमेश ठाकुर, श्रेयांश जैन , अनील सिंह,एस मोहन राव और पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सुमित मजूमदार उपस्थित थे। कार्यक्रम में नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह, रायपुर जिला संघ के सचिव अनूप यदु एवं एनएफआई ऑब्जर्वर पवन पटले की विशेष उपस्थिति रही। प्रतियोगिता को सफल बनाने में प्रदेश के विभिन्न जिला संघों के पदाधिकारियों ने सक्रिय योगदान दिया, जिनमें दुर्ग जिला सचिव मोहनराव, धमतरी जिला सचिव गोपाल साहू, सरगुजा जिला सचिव रजत सिंह, सूरजपुर जिला सचिव राहुल सिंह, जशपुर जिला सचिव खुशबू गुप्ता, कोरबा जिला अध्यक्ष खुशबू राठौर, बलौदा बाजार-भाटापारा से संदीप वर्मा, राजनांदगांव से ऋषि मेश्राम, गरियाबंद से अनिल सिंह, शक्ति से चंद्र प्रकाश तिवारी, रायगढ़ से अभिषेक गुप्ता, कांकेर से सुनील सिंह और मुंगेली से स्वप्निल चुनेकर प्रमुख रूप से शामिल रहे।

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी आम लोगों की समस्याएं

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर।संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आज आयोजित कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में बालोद जिले के विभिन्न स्थानों से अपने मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु पहुँचे आम नागरिकों के लिए राहत भरा साबित हुआ।इस दौरान कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले के विभिन्न स्थानों से पहुँचे लोगों से मधुर एवं आत्मीय बातचीत कर उनकी मांगों एवं समस्याओं की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तलब कर आवेदकों के मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।जनदर्शन में आज डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम खपरी के श्री तारण कुमार ने किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने, गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम कचांदुर के लक्ष्मी बाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, ग्राम नवागांव के श्री खेमलाल ने श्रम कार्ड बनाने, गुरूर विकासखण्ड के ग्राम पलारी के शकुंतला ने राशन कार्ड में नाम जोड़ने, ग्राम हड़गहन के श्री कोमल ने ऋण पुस्तिका में सुधार कराने, ग्राम अंगारी के सरपंच ने मुक्तिधाम में सोलर लाईट लगाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए। जनदर्शन में आज जिले के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर से मुलाकात करने पहुँचे थे।कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जनदर्शन में पहुँचे लोगों से बारी-बारी से मुलाकात कर पूरी आत्मीयता से उनके मांगों एवं समस्याओं को सुना। श्रीमती मिश्रा ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से जनदर्शन में पहुँचे लोगों के मांगों एवं समस्याओं के समुचित निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

पशुधन विभाग ने घर घर जाकर पशुओं को लगाए ९२ हजार से अधिक टीके

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर।पशुधन को खुरपका-मुंहपका, गलघोंटू, और लंगड़ा बुखार जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए समय पर टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय है। इससे न केवल पशुओं की असमय मृत्यु रुकती है, बल्कि उनका दूध व मांस उत्पादन भी सुरक्षित रहता है। पशु चिकित्सा टीकों का महत्व सुरक्षित और कुशल खाद्य उत्पादन तथा पशुओं और मनुष्यों में उभरती और दुर्लभ बीमारियों के नियंत्रण में निहित है। पशु चिकित्सा टीकों का उपयोग पशुधन और मुर्गीपालन में पशु स्वास्थ्य बनाए रखने और समग्र उत्पादन में सुधार के लिए किया जाता है। मानसून की पहली दस्तक के साथ ही बस्तर के वनांचल जिले नारायणपुर में पशुपालकों की धड़कनें तेज हो जाती थीं। बारिश की फुहारों के साथ घड़सरा, एकटंगिया, लंपी स्किन डिजीज और एंटेरोटॉक्सिमिया जैसी जानलेवा संक्रामक बीमारियों का साया मंडराने लगता था। ये बीमारियां न केवल पशुओं का स्वास्थ्य छीनती थीं, बल्कि दूध उत्पादन घटाकर और इलाज का खर्च बढ़ाकर गरीब पशुपालकों की आजीविका पर भी भारी चोट करती थीं। लेकिन इस वर्ष मानसून की शुरूआत में ही नारायणपुर जिले ने बीमारी के इस खतरे के खिलाफ एक मजबूत श्सुरक्षा कवचश तैयार कर लिया। राज्य शासन की मंशा के अनुरूप कलेक्टर के मार्गदर्शन और उपसंचालक के नेतृत्व में पशुधन विकास विभाग ने 1 जुलाई 2026 से जिलेभर में एक वृहद व सघन निःशुल्क टीकाकरण अभियान का आगाज किया।विभाग की 10 पशु चिकित्सालय एवं औषधालयों की टीमों ने केवल कस्बों तक सीमित न रहकर दूरस्थ, दुर्गम और वनांचल गांवों का रुख किया। बारिश की परवाह किए बिना मैदान में उतरे अमले ने न केवल चौपालों पर जागरूकता फैलाई, बल्कि श्डोर-टू-डोरश पहुंचकर पशुधन को सुरक्षा टीके लगाए। विभाग की इस सक्रियता और मुस्तैदी के परिणामस्वरूप जिले में 92,000 से अधिक टीके सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं। जिसमें घड़सरा रोधक टीकेः 51,893, लंपी स्किन डिजीज टीके 27,679,एंटेरोटॉक्सिमिया टीके 8,655, एकटंगिया रोधक टीके 4,650 तथा संक्रमण के अन्य खतरों को मात देने के लिए 11,013 पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलाई गई

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत सीताराम पटेल कोग्राफ्टेड बैंगन से मिली आर्थिक समृद्धि

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर।महासमुंद जिले के सरायपाली विकासखंड के ग्राम पंडरीपानी के किसान श्री सीताराम पटेल ने उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सलाह को अपनाकर सीमित क्षेत्र में भी अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त की है। किसान श्री सीताराम पटेल बताते हैं कि वे पहले पारंपरिक तरीके से धान की खेती करते थे। धान की खेती में मजदूरी, खाद और कीटनाशकों पर अधिक खर्च होने के बावजूद अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता था। बेहतर आय की तलाश में उन्होंने उद्यानिकी विभाग से संपर्क किया। विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में उन्होंने वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्राफ्टेड बैंगन की खेती प्रारंभ की। खेती में उन्होंने ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया। इन तकनीकों से पानी की बचत हुई, खरपतवार नियंत्रण आसान हुआ तथा पौधों की बेहतर वृद्धि के कारण उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जहां पहले धान की फसल से लगभग 18 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलता था, वहीं ग्राफ्टेड बैंगन से लगभग 300 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन प्राप्त हुआ। इस नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 30 हजार रुपये की अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में प्रदान की गई। श्री पटेल ने अपने उत्पाद का विक्रय सरायपाली एवं ओडिशा की मंडियों में किया, जहां उन्हें लगभग 31 रुपये प्रति किलोग्राम का अच्छा मूल्य मिला। इस खेती में प्रति एकड़ लगभग 18 हजार रुपये की इनपुट लागत, 7 हजार रुपये श्रमिक लागत तथा अन्य खर्चों सहित कुल लागत लगभग 30,800 रुपए रही।इसके बावजूद उन्हें लगभग 3 लाख रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, जो पारंपरिक खेती की तुलना में कई गुना अधिक है।श्री सीताराम पटेल की सफलता से ग्राम पंडरीपानी सहित आसपास के क्षेत्रों के किसान भी उद्यानिकी फसलों और आधुनिक खेती की तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

विशेष लोक अदालत में 32 प्रकरण निराकृत, 73.43 लाख रुपये की अवार्ड राशि पारित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला न्यायालय मुंगेली एवं तहसील न्यायालय लोरमी में परक्राम्य लिखित अधिनियम (चेक बाउंस) प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराते हुए कुल 32 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 73 लाख 43 हजार 595 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। जिला न्यायालय में विशेष लोक अदालत का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, पक्षकार एवं न्यायालयीन अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए जिला न्यायालय मुंगेली में तीन तथा तहसील न्यायालय लोरमी में एक, कुल चार खंडपीठों का गठन किया गया। विशेष लोक अदालत के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम (चेक बाउंस) से संबंधित 152 लंबित प्रकरणों को चिन्हित कर सुनवाई के लिए रखा गया।

1000 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में रायपुर का कारोबारी महेंद्र गोयनका गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर ।यूरो कंपनी से जुड़े करीब 1000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता पुलिस ने रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी को दिल्ली की अदालत में पेश करने के बाद 10 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार, महेंद्र गोयनका पर आरोप है कि उसने मध्यप्रदेश के भाजपा विधायक संजय पाठक के परिवार की कंपनियों में फर्जी दस्तावेज और जाली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर कंपनी के नियंत्रण और करोड़ों रुपये की संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश की। शिकायतकताओं हरनीत लांबा और सुरेंद्र सलूजा ने कटनी के कोतवाली और माधवनगर थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं, कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में होने के कारण वहां भी मामला दर्ज किया गया था।शिकायत के मुताबिक, यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में प्रबंधकीय पद पर रहते हुए महेंद्र गोयनका ने अपनी पत्नी और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए।आरोप है कि उसने कंपनी के दो डायरेक्टरों को हटाकर उनकी जगह चार नए डायरेक्टर नियुक्त करवा दिए और वित्तीय लेन-देन में अनियमितता कर करोड़ों रुपये का गबन किया। जांच एजेंसियों का दावा है कि पूरे मामले में करीब 1000 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी हुई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवप्रवेशी बच्चों का किया आत्मीय स्वागत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर, दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जामगांव (एम) में उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय थे। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चन्द्राकर, साजा विधायक श्री ईश्वर साहू, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश पाण्डेय, तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र साहू, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, दुर्ग संभाग आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर, पुलिस महानिरीक्षक श्री अभिषेक शांडिल्य, आयुक्त समग्र शिक्षा श्रीमती किरण कौशल तथा कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह भी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं अतिथियों ने विद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले बच्चों का तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कराकर आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने कक्षा पहली, छठवीं एवं नवमी के चयनित विद्यार्थियों को पुस्तकों एवं गणवेश का वितरण किया तथा कक्षा नवमी की पात्र छात्राओं को सायकल प्रदान की। कक्षा पहली के नवप्रवेशी विद्यार्थियों में भूपेन्द्र सिंह पहाड़ी, पार्थ यादव, वीर चंद्राकर, विवान ठाकुर, यश मारकंडे, डाली सिन्हा, दिव्यांशी, लावन्या साहू, लिशिका चंद्राकर एवं मानवी सेन शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे मन लगाकर अध्ययन करें और अपने ज्ञान, प्रतिभा एवं संस्कारों से समाज और प्रदेश का नाम रोशन करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिक्षा ही विकास का मूल मंत्र है और राज्य सरकार प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और जीवन में सफलता का सबसे सशक्त आधार है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्मार्ट क्लास, समय पर पुस्तक एवं गणवेश वितरण, अतिरिक्त पौष्टिक आहार, नियमित पालक-शिक्षक बैठक, न्योता भोज जैसी अनेक अभिनव पहले संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री से ने कहा कि राज्य में वर्तमान में 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं तथा 24 नालंदा परिसर विकसित किए जा चुके हैं। दिल्ली में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 200 सीट क्षमता वाले छात्रावास की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण के बाद प्रदेश में कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है तथा बस्तर सहित दूरस्थ क्षेत्रों में भी शिक्षा के नए केन्द्र विकसित किए जा रहे हैं। जगरगुंडा में एजुकेशन हब विकसित किया जा रहा है, जिससे वहां के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने प्राचीन गुरुकुल परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा का महत्व सदैव सर्वोच्च रहा है और राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से पढ़ाई के साथ संस्कार, कौशल और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए गए हैं और आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का होगा। आने वाले समय में प्रदेश के 9 हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास प्रारंभ किए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिल्ली में 200 सीटर ट्राइबल यूथ हॉस्टल संचालित किया जा रहा है, जहां इस साल 13 विद्यार्थियों ने यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए अनेक नवाचार कर रही है। शिक्षा गुणवत्ता अभियान के बेहतर परिणाम सामने आए हैं और बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी उल्लेखनीय रहे हैं।उन्होंने कहा प्रदेश में सभी विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था विकसित की जा रही है।प्राथमिक स्तर पर हिन्दी, मध्य स्तर पर अंग्रेजी तथा गणितीय दक्षता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बालिकाओं के लिए 8 हजार से अधिक शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है।

संसद का मानसून सत्र इस बार 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में कुल 25 दिनों में 19 बैठकें होंगी। मोदी सरकार विदेशी अंशदान (नारेबाजी/चंदे) विनियमन संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के अपमान पर 3 साल की सजा का बिल जैसे कई नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। वहीं, मानसून सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दल नीट-यूजी पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद, ई-20 ईंधन और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। ऐसे में सवाल उठना लाज़िमी है कि क्या संसद का यह सत्र भी एक बार फिर विपक्ष के प्रदर्शन और हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या इस बार देश को सार्थक और सकारात्मक विमर्श देखने को मिलेगा। संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच संवाद, सहमति और संसदीय नियमों का पालन आवश्यक है। संसद की गरिमा तभी बहाल हो सकती है, जब सत्ता पक्ष विपक्ष को पर्याप्त सम्मान और समय दे तथा विपक्ष भी केवल विरोध के लिए विरोध करने के बजाय रचनात्मक आलोचना का मार्ग चुनें। ***इन्हीं मुद्दों की पड़ताल करता आजकल का यह खास अंक...***

मानसून सत्र के लिए आत्म अवलोकन जरूरी

विश्लेषण
डॉ. चन्द्र त्रिखा
वरिष्ठ स्तंभकार

यह लगभग साढ़े तीन दशक पहले की बात है। उन दिनों की संसदीय जिन्दगी में सांसदों के पास न तो लैपटॉप थे, न 'गूगल' की त्वरित सुविधा और न ही सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष के पास अपने कोई भारी-भरकम मीडिया-वॉर रूम थे। पुरानी कतरनें एकत्र करने वाला कोई अत्याधुनिक तंत्र भी तब मौजूद नहीं था। मगर उन दिनों एचवी कामथ, नाथ पई, मधु लिमये, मधु दंडवते, डॉ. राममनोहर लोहिया और आचार्य कृपलानी सरीखे ऐसे प्रखर सांसदों की मौजूदगी, सत्ता पक्ष को भी सदा मुस्तैद व जवाबदेह बनाए रखती थी। नेहरू-लोहिया के मध्य 'साढ़े 5 आना औसत आय' और कृपलानी व नेहरू के मध्य कृष्ण मेनन प्रकरण पर होने वाली बहसें आज भी प्रासंगिक हैं और संसदीय दिशा की सच्ची सूचक हैं। तब ये दिग्गज जब सदन में प्रवेश करते थे, तो अपने तर्क के पक्ष में नियमित 'होमवर्क' भी करते थे और उनके दोनों हाथों में संदर्भ पुस्तकें होती थीं।

मगर अब इन सब बातों की कोई आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। क्योंकि आज ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यवाहियों का एजेंडा पहले से ही तयशुदा होता है। प्रतिपक्ष को अक्सर लगता है कि चर्चा एवं खबरों में बने रहने का एकमात्र सुलभ उपाय, संसदीय कार्य में बाधा डालना है। सदन का बहिष्कार करना, नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना और शोर का स्वर ऊंचा ले जाना ही प्रासंगिक बने रहने का एकमात्र तरीका मान लिया गया है। इस सबके लिए यदि सदन से बाहर भी आना पड़े तो वहां भी मीडिया कवरेज भरपूर मिल ही जाती है। इसी परिवर्तित राजनीतिक पृष्ठभूमि में, जब भी मानसून अपने साथ राहत की फुहारें लेकर आता है, सम्पूर्ण राष्ट्र की निगाहें दिल्ली के सत्ता-गलियारों और विशेषकर संसद के मानसून सत्र पर टिक जाती हैं। भारतीय लोकतंत्र का हृदय हमारी संसद है, जहां देश की दिशा और दशा तय होती है। हर बार की तरह इस बार भी एक यक्ष प्रश्न पूरे देश के मानस पटल पर गूंज रहा है कि क्या संसद का यह सत्र भी एक बार फिर विपक्ष के प्रदर्शन और हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या इस बार देश को सार्थक और सकारात्मक विमर्श देखने को मिलेगा।

आज ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यवाहियों का एजेंडा पहले से ही तयशुदा होता है। प्रतिपक्ष को अक्सर लगता है कि चर्चा एवं खबरों में बने रहने का एकमात्र सुलभ उपाय, संसदीय कार्य में बाधा डालना है। सदन का बहिष्कार करना, नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना और शोर का स्वर ऊंचा ले जाना ही प्रासंगिक बने रहने का एकमात्र तरीका मान लिया गया है। इस सबके लिए यदि सदन से बाहर भी आना पड़े तो वहां भी मीडिया कवरेज भरपूर मिल ही जाती है। इसी परिवर्तित राजनीतिक पृष्ठभूमि में, जब भी मानसून अपने साथ ग्रीष्म ऋतु की तपन से राहत की फुहारें लेकर आता है, सम्पूर्ण राष्ट्र की निगाहें दिल्ली के सत्ता-गलियारों और विशेषकर संसद के मानसून सत्र पर टिक जाती हैं। भारतीय लोकतंत्र का हृदय हमारी संसद है।

ज्वलंत मुद्दों की लंबी श्रृंखला

यह प्रश्न केवल एक राजनीतिक जिज्ञासा मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत के कोटि-कोटि करदाताओं की उस गहरी चिंता का प्रकटीकरण है जो वे अपने द्वारा चुने गए जन-प्रतिनिधियों से रखते हैं। विगत कुछ वर्षों के संसदीय इतिहास के पन्नों को यदि हम पलटें तो एक अत्यंत निराशाजनक चित्र उभर कर सामने आता है। संसद के सत्र, चाहे वह शीतकालीन हो, बजट हो या मानसून, प्रायः शोरगुल, अध्यक्ष के आसन के समीप आकर की जाने वाली नारेबाजी और अंततः अनिश्चित काल के लिए कार्यवाही स्थगित होने के गवाह बने हैं।

विपक्ष के पास सदैव सरकार को घेरने के लिए ज्वलंत मुद्दों की एक लंबी श्रृंखला होती है। चाहे वह बढ़ती महंगाई का विषय हो, बेरोजगारी की चुभती समस्या हो, केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील प्रसंग हों।

राष्ट्रहित को मिले सर्वोच्च प्राथमिकता

जब सरकारें विपक्ष की चिंताओं को उदारतापूर्वक सुनती हैं और विपक्षी नेताओं के साथ नेपथ्य में अनौपचारिक संवाद स्थापित करती हैं, तो प्रायः बड़े से बड़े गतिरोध भी बर्फ की भांति पिघल जाते हैं। इन गंभीर परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, यह समय की सबसे बड़ी मांग है कि हमारे जन-प्रतिनिधि यह आत्मसात करें कि संसद कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं, अपितु राष्ट्रीय विमर्श का सर्वोच्च और पवित्र मंदिर है। इस मानसून सत्र से सम्पूर्ण राष्ट्र को यह अपेक्षा है कि विपक्ष अपना विरोध अवश्य दर्ज करे, परंतु तर्कों और प्रामाणिक तथ्यों की कसौटी पर। सरकार को भी विपक्ष के तीखे प्रश्नों का धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए और बिना किसी राजनीतिक दंभ के उनका उचित व पारदर्शी उत्तर प्रदान करना चाहिए। अंततः, यह प्रश्न अपनी जगह अडिग है कि क्या यह मानसून सत्र एक बार फिर विपक्ष के प्रदर्शन की वेदी पर स्वाहा हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर पूर्णतः इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता और विपक्ष, दोनों ही पक्ष अपने राजनीतिक अहंकार और दलगत स्वार्थों को किनारे रखकर राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं या नहीं। यदि दोनों ही पक्ष यह स्मरण रखें कि वे उस भव्य इमारत में इसलिए आसीन हैं क्योंकि देश की सवा सौ करोड़ से अधिक जनता ने उन पर अपना अटूट विश्वास जताया है तो निश्चित ही यह सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने के बजाय भारत की प्रगति का नया अध्याय लिखेगा।

सशक्त और मुखर हो विपक्ष

विपक्ष का निरंतर यह तर्क रहता है कि सरकार सदन में उनके स्वर को दबाने का प्रयास कर रही है, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा से पलायन कर रही है और बिना किसी सार्थक बहस के कानूनों को पारित करवा रही है। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष का यह मुखर आरोप होता है कि विपक्ष जानबूझकर राष्ट्र के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसके पास कोई ठोस तर्क नहीं है और वह केवल राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। इस निरंतर चलने वाले आरोप-प्रत्यारोप के मध्य हमें यह कदापि विस्मृत नहीं करना चाहिए कि लोकतंत्र बिना एक सशक्त और मुखर विपक्ष के नितांत अधूरा है। प्रदर्शन करना, अपनी असहमति प्रकट करना और विरोध दर्ज कराना विपक्ष का नैसर्गिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परंतु विरोध और व्यवधान के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण लक्ष्मण रेखा होती है।

बहस के लिए तत्पर रहे सरकार

जब लोकतांत्रिक विरोध, अनियंत्रित व्यवधान में परिवर्तित हो जाता है तो विपक्ष अनजाने में उसी सर्वोच्च मंच को नष्ट कर देता है जो उसे सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए प्रदान किया गया है। संसद में प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसे बहुमूल्य प्रहर होते हैं, जब जन-प्रतिनिधि सीधे मंत्रियों से जवाब तलब कर सकते हैं। यदि सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है तो विपक्ष सरकार का उत्तरदायित्व तय करने का अपना सबसे अचूक अस्त्र स्वयं ही त्याग देता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह कथन आज भी प्रासंगिक है कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, किंतु राष्ट्र सर्वसम्मति से चलता है। सत्ता पक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर और सम्मान प्राप्त हो। यदि विपक्ष किसी विशेष और ज्वलंत मुद्दे पर विमर्श की मांग कर रहा है, तो सरकार को संसदीय नियमों की परिधि में उस पर खुली बहस के लिए तत्पर रहना चाहिए।

सदन में लगातार विरोध से विपक्ष की गिरती साख

व्यवधान
चरणजीत चरण
स्वतंत्र पत्रकार

दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में वहां की संसद को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र में संसद का स्थान किसी भी धर्मस्थल से ऊपर माना गया है, क्योंकि संसद ही वह स्थान है जहां आम जनमानस की समस्याओं के निवारण के कानून बनते हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को ध्यान में रखकर किसी भी विषय पर चर्चा-परिचर्चा होती है। उसके बाद जनप्रतिनिधियों के वोट के आधार पर कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। जब से देश में संविधान लागू हुआ है यह प्रक्रिया अत्यंत सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ रही है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को विश्व की सबसे सुदृढ़ और पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। आज, जब पूरी दुनिया हमारे लोकतंत्र को एक मानक मानकर अपने देश में लोकतांत्रिक सुधार कर रही है। तब हमारे देश के लोकतंत्र में कुछ अनावश्यक त्रुटियां जगह बना रही हैं।

संसद का काम होता है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से देश की जनता की नब्ज टटोलना, फिर उन समस्याओं के निवारण के लिए कानून बनाना। कानून बनाने की इस प्रक्रिया को एक सकारात्मक और आलोचनात्मक बहस से गुजरना आवश्यक है। अगर कोई कानून संसद में पर्याप्त बहस के बिना कानून का रूप ले लेगा तो वह कुछ लोगों को तो संतुष्ट कर सकता है, लेकिन देश के विकास की गति में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका कई मायनों में सत्ता पक्ष से भी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि सत्तापक्ष में बैठे लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष अपनी रचनात्मक भूमिका नहीं निभाता तो सरकार निरंकुश हो जाती है। पिछले कई वर्षों से यह देखा गया है कि विपक्ष जो विरोध करता है, वह रचनात्मक न होकर नकारात्मक होता है। विरोध की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। तथ्यों और तर्क के आधार पर विरोध स्वीकार्य होता है। उसे सुना भी जाता है और उससे कुछ सकारात्मक व रचनात्मक निर्णय लेने में आसानी होती है। वर्तमान समय में होने वाला विपक्ष का विरोध, विरोध कम और व्यवधान अधिक होता है। विपक्ष का सजग होना और मुखर होना दोनों आवश्यक हैं। विपक्ष का काम है आईना बनकर सरकार के समक्ष खड़े रहना। सरकार की कमियों को उजागर करना और अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे जनता के बीच तक ले जाना। लेकिन यही विरोध जब अपनी मर्यादा लाँघकर अनियंत्रित होने लगे, अभद्रता और हठधर्मिता पर उतर आए तो इसका मतलब होता है कि विपक्ष अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल है। संसद शुरू होने के पहले दिन से ही बिना किसी उचित कारण के तख्तियाँ और बैनर लेकर कुर्सियों पर खड़े हो जाना, लगातार नारेबाजी करना ,अध्यक्ष के आसन के सामने खड़े होकर शोर मचाना और इसी शोर शराबे के कारण संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करा देना न तो सरकार के पक्ष में होता है न ही विपक्ष के। इससे हर रोज जनता के टैक्स का लाखों रुपया बर्बाद होता है और बहुत से जनहित के विधेयक या तो लम्बे समय के लिए लटक जाते हैं या सरकार उन्हें बगैर किसी चर्चा के पास करा देती है जिसके कारण उन विधेयक में रचनात्मक सुधार की गुंजाईश समाप्त हो जाती है। इस प्रकार देश की जनता को मिलता है एक अधकचरा, अपरिपक्व कानून। जिसके दूरगामी परिणाम देश की जनता को झेलने पड़ते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी क़ानून के प्रावधानों को लेकर जनता में जाकर विरोध करना विपक्ष का कर्तव्य है। लेकिन देश की जनता यह भी पूछती है कि जब कानून बन रहा था उस वक्त विपक्ष कहाँ था। क्या संसद के गलियारे में खड़े होकर नारे लगा रहा था या कानून पर कोई रचनात्मक चर्चा कर रहा था। संसद का मंच सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए और सरकार से जवाब मांगने के लिए है। शून्यकाल और प्रश्नकाल के द्वारा जनप्रतिनिधि सीधे सरकार के नुमाइंदों से जवाब मांग सकते हैं। जनता की मूलभूत समस्याएं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क, राशन होती हैं।

विपक्ष को अपनी खोई हुई गरिमा फिर से प्राप्त करनी है तो उसे अपने विरोध का तरीका भी बदलना होगा। विपक्ष को समझना होगा कि विरोध रचनात्मक और तर्कसंगत हो न कि सिर्फ हंगामे के लिए। पूरी संसदीय प्रक्रिया को ठप कर देना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

इन समस्याओं पर सरकार से निरंतर प्रश्न करते रहना विपक्ष का मूल एजेंडा होना चाहिए। साथ ही राजमार्ग का निर्माण, रेल, नदी जल बंटवारा, राज्य सीमा विवाद, साम्प्रदाइक सौहार्द, विदेश नीति, दूसरे देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध, ये सभी किसी भी देश के लिए ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो विपक्ष के सहयोग के बिना नहीं हो सकते हैं। इन विषयों पर चर्चा के समय अगर विपक्ष हंगामा करता है तो फिर जनता का विपक्ष के प्रति मोहभंग होता है। जनता भली-भांति समझती है कि विरोध तथ्यों और तर्कों के आधार पर है या सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए है। निष्कर्ष यही है कि विपक्ष को अपनी कार्यशैली पर विचार करना चाहिए। अगर विपक्ष को अपनी खोई हुई गरिमा फिर से प्राप्त करनी है तो उसे अपने विरोध का तरीका भी बदलना होगा। विपक्ष को समझना होगा कि विरोध रचनात्मक और तर्कसंगत हो, न कि सिर्फ हंगामे के लिए। विरोध के लिए पूरी संसदीय प्रक्रिया को ठप कर देना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। विपक्ष को चाहिए कि वह अपने तर्कों को और मजबूत करे, संसद में रचनात्मक बहस के द्वारा सरकार की नीतियों का विरोध करे यही जनता के हित में है। इसलिए आवश्यक है कि संसद की कार्यवाही निर्बाध रूप से चलती रहे। यही देश हित में है।

पक्ष व विपक्ष में बने व्यावहारिक संतुलन

मानसून सत्र
डॉ. विजेंद्र कुमार
वरिष्ठ स्तंभकार

भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में जब भी नए सत्र की शुरुआत होती है, तो पूरे देश की निगाहें स्वाभाविक रूप से उस पर टिक जाती हैं। वर्तमान परिदृश्य में, संसद का यह सत्र केवल दैनिक कामकाज का गवाह बनने वाला नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य की आधारशिला रखने वाले दो ऐतिहासिक विषयों- परिसीमन विधेयक और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर निर्णायक चर्चा का केंद्र बनने जा रहा है। आज हर किसी के मन में यह सवाल है कि क्या सरकार इस मानसून सत्र में इन दोनों बड़े बदलावों को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगी।

देश के चुनावी भूगोल को बदल देने वाले इन विधेयकों का भविष्य अंततः इस बात पर निर्भर करेगा कि सदन के भीतर सरकार की रणनीति और विपक्ष की असहमति के बीच कैसा व्यावहारिक संतुलन स्थापित होता है। यदि हम परिसीमन विधेयक को समझें, तो यह केवल भौगोलिक सीमाओं का बदलाव नहीं है, बल्कि बदलती जनसंख्या के आधार पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को अद्यतन करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके तहत लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 तक करने का अभूतपूर्व प्रस्ताव रखा गया है। इसका सबसे संवेदनशील पहलू जनसंख्या से जुड़ा है, जिससे विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि जनसंख्या नियंत्रण में उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण संसद में उनका प्रतिनिधित्व घट सकता है। हालांकि, गृह मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि नए परिसीमन से किसी भी दक्षिणी राज्य को नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनका आनुपातिक हिस्सा बरकरार रहेगा और कुल सीटों में भी वृद्धि होगी। इसके बावजूद, क्षेत्रीय दल इसे राज्यों के अधिकारों से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक नई राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस सत्र में इस विधेयक को पारित करा सकेगी। इसे पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। लोकसभा में सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त संख्याबल है, लेकिन राज्यसभा के आंकड़े और सहयोगी दलों की अपेक्षाओं को साधना एक कठिन चुनौती है। हालांकि, सत्तारूढ़ दल की कार्यप्रणाली में चौंकाने वाले निर्णयों का एक लंबा इतिहास रहा है, इसलिए राजनीति के इस खेल में किसी भी संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता।

इसी सरगर्मी के बीच, इस सत्र का दूसरा बड़ा मुद्दा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की दूरगामी संकल्पना है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की ठोस वकालत की है। इसका तर्क है कि इससे हजारों करोड़ रुपये की भारी बचत होगी और बार-बार आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। वहीं, इसके विपरीत विपक्ष और कई विश्लेषकों का तर्क है कि एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रीय मुद्दों की आंधी में स्थानीय समस्याएं पूरी तरह दब जाएंगी। उन्हें डर है कि मतदाता एक ही पार्टी के पक्ष में एकतरफा मतदान कर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों का स्वतंत्र अस्तित्व और देश का संघीय ढांचा कमजोर हो सकता है। इन दोनों महत्वाकांक्षी विधेयकों की राह में केवल संसदीय गणित ही एकमात्र बाधा नहीं है, बल्कि संवैधानिक संशोधनों की वह जटिल प्रक्रिया भी है जिसमें राज्यों की प्रत्यक्ष भागीदारी अनिवार्य होती है। विशेष रूप से 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संकल्पना को साकार करने के लिए संविधान के कई महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में व्यापक संशोधन की आवश्यकता होगी। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, जहां कई प्रमुख राज्यों में विपक्षी दलों की मजबूत सरकारें आसीन हैं, वहां से इस विधेयक के पक्ष में समर्थन जुटाना केंद्र सरकार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि यह मानसून सत्र भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक पड़ाव बनने जा रहा है। परिसीमन और समकालिक चुनाव, दोनों ही ऐसे परिवर्तनकारी कदम हैं, जिनके लिए केवल साधारण बहुमत नहीं, बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अपने राजनीतिक कौशल से इस जटिल चक्रव्यूह को भेद पाती है या विपक्ष एकजुट होकर इन विधेयकों को फिलहाल रोकने में सफल रहता है। पूरे देश को प्रतीक्षा है कि पक्ष और विपक्ष राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर इन गंभीर विषयों पर परिपक्व विमर्श प्रस्तुत करेंगे।

यह मानसून सत्र भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक पड़ाव बनने जा रहा है। परिसीमन और समकालिक चुनाव, दोनों ही ऐसे परिवर्तनकारी कदम हैं, जिनके लिए केवल साधारण बहुमत नहीं, बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है।

सांसदों के दैनिक भत्तों में करें कटौती

आर्थिकी
डॉ. पवन कुमार शर्मा
स्वतंत्र पत्रकार

भारतीय संसद देश की संप्रभुता, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन-आकांक्षाओं का प्रतीक है। पिछले कुछ दशकों में संसद के भीतर बढ़ते गतिरोध और घटती उत्पादकता ने करदाताओं की धनराशि के सदुपयोग और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। भारतीय संसद को चलाने में भारी जन-धन का व्यय होता है। हालिया बजटीय आकलनों और संसदीय आंकड़ों के अनुसार, संसद के दोनों सदनों लोक सभा और राज्य सभा को सुचारू रूप से चलाने का अनुमानित खर्च लगभग 2.5 लाख प्रति मिनट यानी 1.5 करोड़ प्रति घंटा आता है। इस हिसाब से एक दिन की सामान्य कार्यवाही का खर्च करीब 9 करोड़ तक पहुंच जाता है। इस खर्च में सांसदों के वेतन-भत्ते, संसद भवन का रखरखाव, सुरक्षा, सचिवालय का स्टाफ, मुद्रण और सत्र के दौरान होने वाले अन्य प्रशासनिक खर्च शामिल हैं। जब सदन में व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित होती है तो यह पूरा पैसा बिना किसी विधायी परिणाम के व्यर्थ हो जाता है।

क्या संसद न चलने पर सांसदों का भत्ता काटा जाना चाहिए? यह मुद्दा भारतीय लोकतंत्र में ज्वलंत बहस बन चुका है। इसके दो मुख्य पहलू हैं। सकारात्मक पक्ष (भत्ता काटे जाने के) यह है कि कॉरपोरेट या किसी भी संगठित क्षेत्र में 'नो वर्क, नो पे' का नियम लागू होता है। जनता का तर्क है कि जब करदाताओं की गाढ़ी कमाई से सांसदों को प्रतिदिन 'सदन उपस्थिति भत्ता' और अन्य सुविधाएं मिलती हैं तो बिना काम किए इसे प्राप्त करना नैतिक रूप से गलत है। व्यवधान के दिनों का भत्ता काटने से सांसदों में जवाबदेही बढ़ेगी। नकारात्मक पक्ष यह है कि संसदीय लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना भी एक वैध उपकरण माना जाता है। कई बार विपक्ष को अपनी बात रखने का समय नहीं मिलता, जिससे मजबूरन वे सदन के बीचों-बीच वेल में आकर प्रदर्शन करते हैं। सांसद का काम केवल संसद में बैठना नहीं होता, वे समितियों में काम करते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं का निवारण भी करते हैं। जब बजट या महत्वपूर्ण कानून बिना किसी बहस के 'गिलोटीन' (बिना चर्चा के पास करना) के जरिए पारित हो जाते हैं तो यह न केवल वित्तीय नुकसान है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी हनन है। 2024 के आम चुनावों के बाद गठित 18वीं लोक सभा में विपक्ष ने पहले की तुलना में अपनी आवाज़ मजबूत की है। इसके प्रारंभिक और बजट सत्रों (2024) में लोक सभा और राज्य सभा क्रमशः 22 और 20 दिनों तक चलीं। हालांकि 2026 के बजट सत्र में विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक के कारण लगभग 20-25 घंटे व्यवधान की भेंट चढ़ गए, जिससे टैक्सपेयर मनी का नुकसान हुआ। नीट परीक्षा विवाद, विभिन्न केंद्रीय मुद्दों पर विपक्ष के तीखे तेवर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और सेना के पूर्व जनरलों की किताबों के अंशों पर सदन में चर्चा को लेकर हुए विवादों ने सदन को बार-बार बाधित किया। भारतीय संसद के इतिहास को देखें तो पहली तीन लोक सभाओं (1952-1967) में वार्षिक बैठकों का औसत 120-130 दिन होता था, जो अब घटकर औसतन 60-70 दिन रह गया है। संसद में होने वाले व्यवधान महज तात्कालिक राजनीतिक विवाद नहीं होते बल्कि इनके पीछे कुछ गहरे संस्थागत और सियासी कारण होते हैं। विपक्ष का अकसर यह आरोप रहता है कि सरकार महत्वपूर्ण और संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा से बचती है। करदाताओं का पैसा देश के निर्माण के लिए है न कि राजनीतिक गतिरोध की बलिवेदी पर चढ़ने के लिए। संसद की उत्पादकता सुधारने और वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए कुछ ठोस सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। न्यूनतम कार्य दिवस तय करना इस दिशा में पहला कदम हो सकता है। यदि कोई सांसद या दल जानबूझकर बिना किसी ठोस विधायी कारण के सदन को लगातार बाधित करता है तो आनुपातिक रूप से उनके दैनिक भत्तों में कटौती का कानून बनना चाहिए। हर महत्वपूर्ण विधेयक को संसद में पारित होने से पहले अनिवार्य रूप से विभाग-संबंधित स्थायी समितियों के पास भेजा जाना चाहिए ताकि उन पर विशेषज्ञता के साथ चर्चा हो सके। संसद की गरिमा, सर्वोच्चता और उत्पादकता तभी बहाल हो सकती है, जब सत्ता पक्ष विपक्ष को पर्याप्त सम्मान और समय दे और विपक्ष भी केवल विरोध के लिए विरोध करने के बजाय रचनात्मक आलोचना का मार्ग चुने।

संसद की उत्पादकता सुधारने और वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए कुछ ठोस सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि कोई सांसद या दल जानबूझकर बिना किसी ठोस विधायी कारण के सदन को लगातार बाधित करता है तो आनुपातिक रूप से उनके दैनिक भत्तों में कटौती का कानून बनना चाहिए।

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०/ /अ-20 (3)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदकगण जय भगवान आ० स्व० भागे राम अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल आ० स्व० भागे राम अग्रवाल, रेखा अग्रवाल आ० स्व० भागे राम अग्रवाल, विमला अग्रवाल आ० स्व० भागे राम अग्रवाल, कान्ता अग्रवाल आ० स्व० भागे राम अग्रवाल तथा चन्द्रदीप अग्रवाल आ० स्व० बजरंग अग्रवाल, शारदा उर्फ श्रद्धा अग्रवाल आ० स्व० बजरंग अग्रवाल, रूचिका अग्रवाल आ० स्व० बजरंग अग्रवाल. रीतु देवी आ० स्व० बजरंग अग्रवाल की ओर से मुख्तारआम सतीश कुमार अग्रवाल आ० स्व० भागे राम अग्रवाल, निवसी सत्तीपारा, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा के द्वारा अपने सयुक्त स्वामित्व की मोहल्ला देवीगंज वार्ड, शीट नम्बर-03 नगर अम्बिकापुर स्थित भूमि 538/3. 839/3 रकबा 0.02 1/2, 0.03 1/4 एकड़ भूमि से अपना हक अनावेदक सतीश कुमार अग्रवाल आ० स्व० भागे राम अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी सत्तीपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर के पक्ष में हक त्याग करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र, अधिकार पत्र (पावर ऑफ अटार्नी) सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 31.07.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांक 14.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-ब-121/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक अमन अग्रवाल माता मधु अग्रवाल, निवासी वार्ड कमांक 16 मुख्य मार्ग सूरजपुर, तहसील सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छ०ग० के द्वारा शीट नम्बर-09 मोहल्ला बाबूपारा, अम्बिकापर, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3467/4866/205 रकबा 1950 वर्गफीट भूमि पर प्रस्तावित नक्शानुसार अनुसार भू-तल पर रकबा 129.80 वर्गमीटर, प्रथम तल पर रकबा 118.06 वर्गमीटर, द्वितीय तल पर 118.06 वर्गमीटर पर आवासीय भवन निर्माण कराने हेतु आवेदन पत्र मय मेन्टेनेन्स खसरा एवं प्रस्तावित नक्शा की प्रति सहित आवेदन पत्र न्यायालय अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ०ग० के समक्ष प्रस्तुत किया है जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 31/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांकः- 15/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2, जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क० / अ-6/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका संतोषी घोष पत्नी भोला घोष व अन्य, निवासी पुराना माईनस कॉलोनी कुम्दा गोविन्दपुर, तहसील लटोरी, जिला सूरजपुर छ०ग० द्वारा ग्राम अजिरमा स्थित भूमि कुल खसरा नंबर 815/7 रकबा 2540 हे0 मेरो रकबा 0.009 है. भूमि जो अना./हक त्यागकर्ता महेश कुमार घोष पिता स्व. मनोरंजन घोष के हक और हिस्से की भूमि का पंजीकृत हक त्याग विलेक दिनांक 11.02.2026 को आवेदिकागण के पक्ष में हक त्यागनामा का निष्पादन किया गया है। आवेदिकागण द्वारा उपरोक्त हक त्याग के आधार पर अनावेदक महेश कुमार घोष पिता स्व. मनोरंजन घोष, जाति कायस्थ, निवासी पुराना माईनस कॉलोनी कुम्दा गोविन्दपुर, तहसील लटोरी, जिला सूरजपुर छ०ग० का नाम विलोपित कराने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 12/08/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 17/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-2

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती गायत्री अग्रवाल आ०/पति सुनील कुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल, निवासी सदर रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-बाबूपारा, शीट नम्बर 9 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3467/4866/233 रकबा 1320 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-28/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 14/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी, जिला जशपुर (छ.ग.)
// ईश्तहार //
क्रमाक / 3755/वाचक-2/अपर कले. / 2026 जशपुर, दिनांक 17/07/2028

सर्व साधारण को इस ईश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सुकदर्शन विश्वकर्मा पिता स्व. परसराम विश्वकर्मा, उम्र 29 वर्ष, जाति लोहार, तहसील व थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.) एवं आवेदिका शबनम तिर्की पिता श्री इलियाजर तिर्की, उम्र 27 वर्ष, जाति उरांव, निवासी ग्राम गलीमार, तहसील धरमजयगढ़, थाना छाल, जिला रायगढ़ (छ.ग.) द्वितीय पक्ष ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 05 के तहत् आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आशयित विवाह की सूचना दी गई है। उक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक 29.07.2026 को दोपहर 03:00 बजे मेरे न्यायालय में होगी।

उभयपक्ष के विवाह के संबंध में जिस किसी को आपत्ति करना हो तो निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 15.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

अपर कलेक्टर
एवं विशेष विवाह अधिकारी
जिला जशपुर (छ.ग.)

रामनिरंजन झुनझुनवाला कॉलेज में स्नातकोत्तर छात्रों का प्रमाणपत्र वितरण समारोह संपन्न

संवाददाता

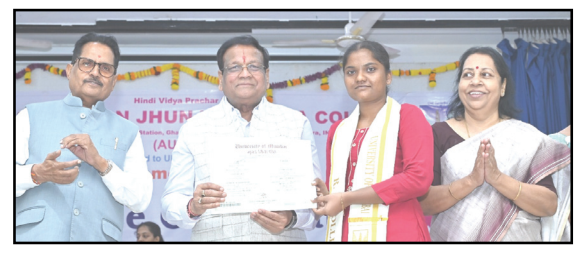

मुंबई, : - हिंदी विद्या प्रचार समिति के रामनिरंजन झुनझुनवाला कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स (अधिकार प्रदत्त स्वायत्त) में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए पदवी प्रमाणपत्र वितरण समारोह शनिवार, 18 जुलाई 2026 को साबू हॉल में गरिमापूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों का उत्साहपूर्वक उत्सव मनाया। समारोह के मुख्य अतिथि आर. आर. केबल लिमिटेड, मुंबई के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार काबरा थे, जबकि हिंदी विद्या प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समिति की निदेशक डॉ. उषा मुकुंदन, प्राचार्य डॉ. हिमांशु दावड़ा, उप-प्राचार्य एवं उप-परीक्षा नियंत्रक कैप्टन प्रो. प्रवीण नायक, उप-प्राचार्य डॉ. स्नेहा देउस्कर तथा डॉ. किरण कोलवणकर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरूआत प्राचार्य डॉ. हिमांशु दावड़ा के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने सभी अतिथियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉ. राजेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों से कहा कि ₹मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आपकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा किसी दूसरे से नहीं, बल्कि स्वयं से होती है।₹ उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर सीखने और उत्कृष्टता की ओर अग्रसर रहने का संदेश दिया। इसके बाद उप-परीक्षा नियंत्रक प्रो. प्रवीण नायक ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि महेंद्र कुमार काबरा ने मेधावी स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को डिग्री प्रमाणपत्र प्रदान किए और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। अपने प्रेरणादायक संबोधन में महेंद्र कुमार काबरा ने ₹वसुधैव कुटुम्बकम₹ और ₹सर्वे भवन्तु सुखिनः₹ के आदर्शों पर चलते हुए समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सफलता केवल मेहनत, अनुशासन और समय का सदुपयोग करने वालों को ही मिलती है तथा बहानेबाजी और टालमटोल से कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। समारोह के अंत में उप-प्राचार्य डॉ. स्नेहा देउस्कर ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारियों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया।

एकनाथ शिंदे की शिवसेना महिला गठबंधन की उप-जिला प्रमुख गिरफ्तार

नवी मुंबई : नवी मुंबई के राजनीतिक गलियारों में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। शिवसेना के शिंदे गुट की महिला अघाड़ी की उप-जिला प्रमुख पूजा बंसोडे को तूर्भे एमआईडीसी पुलिस ने एक स्क्रैप व्यापारी से 2 लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गंभीर आरोप है कि फिरौती देने से इनकार करने पर पूजा बंसोडे और उनके साथियों ने व्यापारी और उसकी दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई की और उन्हें गालियां दीं।

मानसून सत्र में हंगामे के तगड़े आसार: सत्तापक्ष और विपक्ष एक दूसरे को पटखनी देने की जुगत में

नीट पेपर लीक, प्रधान के इस्तीफे, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, बागी सांसदों के मुद्दे पर विपक्ष रहेगा हमलावर

विपक्ष के तीरों को कुंद करने की तैयारी में जुटे सरकार के सिपहसालार

कॉकरोच जनता पार्टी का संसद कूच आज, जंतर मंतर पर युवाओं की भारी भीड़

नई दिल्ली

संसद का मानसून सत्र आज सोमवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान कई मुद्दों को लेकर संसद में भारी हंगामा होने के आसार है। विपक्ष पुरजोर तरीके से सत्तापक्ष पर हमलावर रूख अख्तियार करेगा ऐसी संभावना है। फ्लोर लीडर्स की बैठक में शामिल हुए विपक्षी दलों ने जिस एकजुटता के साथ बैठक से वॉकआउट किया उससे यह संभावना और ज्यादा बढ़ गयी है कि मानसून सत्र की बैठक सुचारू रूप से चलनी मुश्किल होंगी। ज्ञात हो कि कुछ विपक्षी दलों में टूट के कारण बने नए राजनीतिक समीकरणों के बीच संसद का नया सत्र शुरू होने जा रहा है।

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सभी विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की है पर इस बार नीट पेपर लीक धरना, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और बागी सांसदों के मुदें से लेकर बेरोजगारी, ई 20 पट्रोल और अमेरिका का भारत के प्रति कठोर सहित कई मसलों पर सत्तापक्ष और विपक्ष में टकराव हो सकता है।

कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर चल रहे धरने से सोनम वांगचुक को जबरन हटाने को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमला बोलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद की तरफ कूच का ऐलान किया हुआ है। कई विपक्षी नेता धरने पर जाकर सरकार को अलोकतांत्रिक बता चुके हैं। सोमवार को सरकार कूच करने वाले युवाओं से कैसे निपटती है इस पर भी जनता की निगाह रहेगी। विपक्षी दल परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक पर कड़ा रूख अपनाते दिख सकते हैं। परिसीमन संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को हालांकि अभी तक विधायी एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार के भी 'आक्रामक रुख' अपनाने की संभावना है और मानसून सत्र के दौरान उसकी 'प्राथमिकता' विधेयकों को पारित कराने की होगी। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस को हालांकि भरोसा है कि 'इंडिया' गठबंधन के दल इस विधेयक का विरोध जारी रखेंगे।

सरकार निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लागू करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के प्रयास में सक्रिय रूप से जुटी हुई हैं। शरद पवार की एनसीपी समेत कुछ विपक्षी दल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि यदि परिसीमन मसौदा कानून में राज्यों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान किए जाते हैं, तो वे सरकार के इस कदम के लिए तैयार हो सकते हैं। अप्रैल में हुए विशेष सत्र में खारिज हुए 131वें संविधान संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करने वाले द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने भी कहा है कि वह नये मसौदे की समीक्षा करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देगी।

टीएमसी ने उठाए सवाल: किस आधार पर बुलाया गया?

एजेंसी नई दिल्ली

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा एनसीपीआई बनाने वाले 20 बागी टीएमसी सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दिए जाने के बाद विपक्षी दलों ने यह वॉकआउट किया था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार के इस कदम पर तीखे सवाल उठाए। महुआ ने कहा कि स्पीकर ने अब तक इन बागी सांसदों के विलय को मंजूरी नहीं दी है और उनके खिलाफ अयोग्यता की याचिकाएं अभी भी लंबित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि टेबल ऑफिस द्वारा दी गई सूची में टीएमसी के सदस्यों की संख्या कुछ और बताई है। उन्हें किस आधार पर आमंत्रित किया?

एनसीपीआई का तर्क

टीएमसी की आपत्तियों के बीच एनसीपीआई नेता सुदीप बंद्योपाध्याय ने पार्टी की भागीदारी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पार्टी सरकार की ओर से आमंत्रण मिलने के बाद ही इस बैठक में शामिल हुई है। रिजिजू ने 19 अन्य लोकसभा सांसदों को मानसून सत्र से पहले होने वाली इस पारंपरिक सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया था।

पटनायक की नसीहत

पेपर लीक पर छात्रों से संवाद करे सरकार

बीजू जनता दल (बीजेडी) के प्रमुख नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से परीक्षा में कथित गड़बड़ियों का विरोध कर रहे छात्रों से बातचीत शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए। सीजेपी परीक्षा में कथित गड़बड़ीके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है।

डीलिमिटेशन बिल का समर्थन करेगी डीएमके

सर्वदलीय बैठक में परिसीमन बिल को लेकर डीएमके का रुख चर्चा का विषय बन गया। आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने दावा किया कि डीएमके ने बिल का समर्थन किया है। हालांकि, सांसद तिरुची शिवा ने साफ कहा कि सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट प्रस्ताव पेश नहीं किया है। और पार्टी को इस मुद्दे पर सरकार से और स्पष्टता चाहिए। डीएमके ने बैठक में कहा कि महिला आरक्षण को मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या के आधार पर ही तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

जयराम ने साफ की तस्वीर-परिसीमन बिल का समर्थन नहीं करेंगे

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने परिसीमन बिल को लेकर कहा कि कांग्रेस इस विधेयक का समर्थन नहीं कर रही है। जयराम ने चैनल पर दिखाई जा रही खबरों निराधार बताते हुए उन मीडिया हाउसों को आड़े हाथों लिया जो विपक्ष के रुख को लेकर गलत दावे कर रहे हैं। उन्होंने एक्स लिखा, कुछ चैनल फैलाई गई ये खबर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस ने बैठक में विधेयक का समर्थन किया है।

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ आवेदिका श्याम प्रकाश विश्वकर्मा आ०/पति स्व० रामदुलारे विश्वकर्मा व 01 अन्य जाति निवासी केदारपुर गुदरी बाजार रोड़ अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०म० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-केदारपुर गुदरी बाजार रोड़, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1252/4 रकबा 1956 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 30.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 16.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायलय तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ०ग०
ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शोभनाथ राम आ० जीतू राम निवासी रामपुर थाना अम्बिकापुर तहसील ने कराया है कि आवेदक के अपने दीदी (स्व. नर्बदिया रजवाड़े उर्फ आ० जीतू राम की दिनांक 29/11/2018 को मथुरा स्थान निवास में हुई है

आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है। अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 17/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर

वसई विरार में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों से वाहन चालक, राहगीर है परेशान

वसई। वसई-विरार शहर में बारिश के दौरान खस्ताहाल सड़कों और बढ़ते गड्ढों से परेशान नागरिकों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। सड़कों की बदहाल स्थिति, जलभराव और प्रशासन की कथित उदासीनता के कारण सड़क पर चलने वाले वाहन और पैदल चलने वाले नागरिक हो रहे है। बार-बार शिकायतों और लिखित मांगों के बावजूद सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। बारिश शुरू होते ही वसई-विरार की मुख्य और आंतरिक सड़कें बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। कई स्थानों पर एक से डेढ़ फुट गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद्वा रा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका राजेश कुमार अग्रवाल आ०/पति ओम प्रकाश अग्रवाल जाति अग्रवाल, निवासी बगीचा, तहसील बगीचा, जिला जशपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला बाबूपारा, शीट नम्बर 9 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3467/4866/51 रकबा 180 वर्गमीटर भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 28.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांकः- 14/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती प्रभा शर्मा आ०/ पति नरेश शन्को सूचित कियामा नहरू वार्ड सत्तीपारा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-सत्तीपारा, शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 680/4 रकबा 0.02 1/2 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 30.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांकः- 10.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती कल्याणवती चौबे आ०/पति जय प्रकाश चौबे जाति ब्राम्हण, निवासी नेहरू वार्ड सत्तीपारा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला सत्तीपारा, शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 627/14 रकबा 0.03 1/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 28.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 14.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष
ग्राम प.ह.न.
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रवण कुमार पिता ठुंनगुराम जाति पनिका निवासी ग्राम बिरमताल प.ह.न.09 रा.नि.म. शिवप्रसादनगर तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्री - मैनषा का जन्म दिनांक 17/10/2009 बिरमताल में हुई है. अज्ञानतावश जन्म / प्रमाण पत्र। पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने पुत्री मैनषा का जन्म / पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत बिरमताल को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 23/07/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 07/07/2026को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
भैयाथान जिला सूरजपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष
ग्राम प.ह.न.
ईश्तहार

साय एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुखलसाय पिता राजमोहन जाति कवंर निवासी

ग्राम कुसमुसी प.ह.न 11 रा.नि.म. शिवप्रसादनगर भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक की दादी - क्यारो का मृत्यु दिनांक 09/09/2009 को ग्राम. कुसमुसी में हुई है, अज्ञानतावश / मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने दादी - क्यारो का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत कुसमुसी को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 31/07/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक. 16/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगाँव तहसील भटगांव
रा०प्र०कं० 227 ब - 121/2025-2026
ईश्तहार

आम जनता ग्राम बरउल को सूचित किया जाता है कि आवेदक अक्षय लाल आ. मानसाय जाती कुम्हार निवासी ग्राम बरउल तहसील भटगांव जिला सूरजपुर द्वारा अपने बाबा बिरझु का मृत्यु दिनांक 05/05/2002 को मृत्यु होने पर आवेदक द्वारा आपने बाबा का मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत शुलक अदा कर चालान की प्रति, सपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आक्षेप हो तो वह अपना आक्षेप दिनाक 20/07/26 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात्प्राप्त आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। आज दिनांक 09/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
कार्यपालिक भटगांव जिला-सूरजपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती आशा साहू आ०/पति फलेन्द्र प्रसाद साहू जाति निवासी देवीगंज रोड़ बसदेवापारा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला देवीगंज रोड़, शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 342/2, 343/4 रकबा 0.00 3/4, 0.00 3/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक - 30.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 15.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका सरजू आ०/पति रामधन प्रसाद गुप्ता जाति, निवासी देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला देवीगंज रोड़, शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 434/1 रकबा 0.10 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 30.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः 15.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

फिल्म इवेंट

हॉलीवुड

'मुझे हाथ मत लगाओ', फैन ने छू लिया तो भड़क उठे जैकब एलोर्डी

जापान में जैकब एलोर्डी के साथ हुआ एक छोटा सा लेकिन चर्चित वाकया हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, एक वीडियो में देखा गया कि जैकब एलोर्डी जापान के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे, तभी एक फैन उनके पास आया और फोटो लेने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान फैन ने उनकी पीठ पर हाथ रख दिया, जिससे एक्टर थोड़े असहज हो गए। जैकब तुरंत रुक गए, पीछे मुड़े और साफ शब्दों में कहा, 'प्लीज भाई मुझे हाथ मत लगाओ।' इसके बाद वह वहां से चले गए। यह छोटा सा पल कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया। यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर द्वारा शेयर किया गया था। कुछ ही समय में यह क्लिप सोशल मीडिया पर फैल गई और लोगों के अलग-अलग रिएक्शन सामने आने लगे। कुछ लोग जैकब के रिएक्शन को सही ठहरा रहे हैं, तो कुछ इसे ओवररिएक्शन बता रहे हैं। इसी बीच जैकब एलोर्डी अपनी आने वाली फिल्म 'द डॉग स्टार्स' को लेकर भी चर्चा में हैं। इस फिल्म का पहला ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है, जिससे फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है। एक्टर की पर्सनल लाइफ भी इन दिनों सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैकब एलोर्डी का नाम मॉडल केंडल जेनर के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों को लॉस एंजेलिस में साथ देखा गया था और हवाई में छुट्टियां मनाने की खबरों ने इन अफवाहों को और हवा दे दी। हालांकि, अब तक न जैकब और न ही केंडल ने इन खबरों पर कोई आधिकारिक बयान दिया है।

टॉलीवुड

'मां इंटी बंगारम' में खुद सामंथा ने किए हैं सारे एक्शन सीन्स

साउथ अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने 'मां इंटी बंगारम' फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी की हैं। अब इस बीच उन्होंने फिल्म के में किए एक्शन सीन को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु अपनी आने वाली फिल्म 'मां इंटी बंगारम' को लेकर काफी चर्चा में है। यह फिल्म 19 जून को रिलीज हुई है। हाल ही में चेन्नई में हुए एक प्री-रिलीज इवेंट में समांथा ने फिल्म के एक्शन सीन को लेकर दिलचस्प बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में एक्शन बिल्कुल रियल है- ना कोई स्लो मोशन, ना ही उड़ने वाले शॉट्स और ना ही ज्यादा ड्रामा। समांथा ने कहा, 'फिल्म में जो भी फाइट सीन हैं, वो बिल्कुल असली लगेंगे। मुझे भी शूटिंग के दौरान कई बार चोट लगी, यहां तक कि खून भी बहा। लेकिन मैंने सारे एक्शन सीन खुद किए हैं, इसलिए ये इतने असली लगते हैं और लोगों को पसंद आते हैं।'

फिल्म का निर्देशन नंदिनी रेड्डी ने किया है। वहीं सीबीएफसी ने इस फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की मंजूरी दे दी है। फिल्म 'मां इंटी बंगारम' एक फैमिली एक्शन-कॉमेडी ड्रामा है। इस फिल्म को सामंथा के पति और निर्देशक राज निदिमोरु ने बनाया है। इस फिल्म में दिगनाथ और गुलशन देवैया अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इनके अलावा फिल्म में श्री मुखी, गौतमी, आनंद और लक्ष्मी भी सपोर्टिंग रोल में दिखाई देंगे।

भोजपुरी

भोजपुरी की सबसे महंगी अभिनेत्री की बहस फिर छिड़ी

आज के समय में अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित एक्ट्रेसेस में से एक हैं। पॉपुलैरिटी और मोटी कमाई की बदौलत इन दोनों ही एक्ट्रेसेस की लाइफस्टाइल किसी महारानी से कम नहीं है।

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां आज कमाई और लोकप्रियता के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं। हाल ही में अभिनेत्री अक्षरा सिंह, अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम 3' के गाने 'घिस घिस घिस' में अपने डांस को लेकर काफी चर्चा में हैं। आइए जानते हैं भोजपुरी की टॉप अभिनेत्रियों की कुल संपत्ति और उनकी फीस के बारे में।

भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह की कुल संपत्ति कथित तौर पर लगभग 50 से 55 करोड़ रुपये है। अक्षरा भोजुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक हैं। एक फिल्म के लिए अक्षरा सिंह 10 से 40 लाख रुपये की फीस लेती हैं। एक स्टेज शो के लिए अक्षरा 3 से 5 लाख रुपये चार्ज करती हैं। इसके अलावा अक्षरा गानों की रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया विज्ञापन के जरिए भी जमकर कमाई करती हैं। अक्षरा सिंह के पास टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा स्कॉर्पियो और मुंबई में एक आलीशान घर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे की कुल संपत्ति लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये है। आम्रपाली 15 से 30 लाख रुपये प्रति फिल्म चार्ज करती हैं। इसके अलावा आम्रपाली ब्रैंड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया और स्टेज शो से भी मोटी कमाई करती हैं। आम्रपाली के पास रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर जैसी कारों का कलेक्शन है।

रेट्रो की चमक

2026 में रेट्रो फ़ैशन ट्रेंड्स ₹फ़्यूचर-पास्ट₹ रीमिक्स से तय हुए है। जिसमें पुराने दौर और मॉडर्न, सोच-समझकर अपनाए गए स्टाइल का मेल साफ नजर आ रहा है। पूरी तरह से कॉस्ट्यूम जैसे पुराने ज़माने के लुक अपनाने के बजाय, आजकल के स्टाइल में किसी एक खास विंटेज पीस को आज के ज़रूरी कपड़ों के साथ मिलाकर पहनने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

लाइफ स्टाइल

त्वचा को डीप करने के लिए फेशियल की जगह ये चीजें आएंगी काम, खिलेगा चेहरा

गर्मी का मौसम चरम पर है। इस मौसम में अक्सर त्वचा में मौजूद पोर्स में ऑयल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण त्वचा चिपचिपी नजर आने लगती है। आमतौर पर गर्मी ही नहीं, बल्कि त्वचा का निखार खो जाने के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। त्वचा की देखभाल करने के लिए घर में मौजूद चीजें बेहद फायदेमंद होती हैं। तो आइये जानते हैं स्किन को डीप क्लीन करने के लिए घरेलू नुस्खा। साथ ही, बताएंगे इस नुस्खे से त्वचा को मिलने वाले फायदों के बारे में-

कॉफी और खीरा स्किन में मौजूद पोर्स को डीप क्लीन करने में मदद करते हैं। त्वचा से टैनिंग हटाने के काम आती है। स्किन को ब्राइट करने में लाभदायक है। त्वचा के लिए नेचुरल स्क्रब की तरह से काम करती है।

खीरे को चेहरे पर लगाने के फायदे क्या हैं?

खीरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व त्वचा को नमी प्रदान करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद तत्व स्किन को डीप क्लीन करने के काम आते हैं। खीरे में मौजूद मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट तत्व चेहरे पर मौजूद पोर्स का साइज बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं।

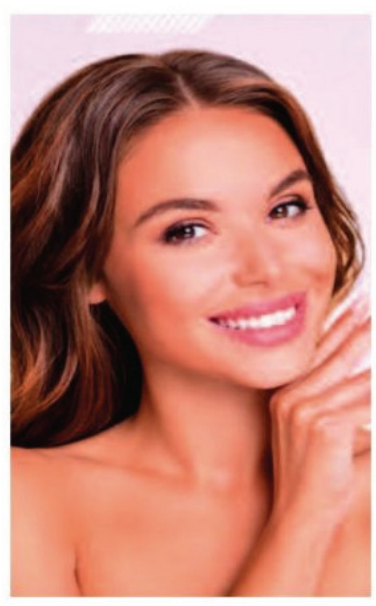

चेहरे की त्वचा को डीप क्लीन करने के लिए घरेलू उपाय

चेहरे की त्वचा को डीप क्लीन करने के लिए सबसे पहले वक खीरे को पीस लें। इसके बाद एक बाउल में आधा चम्मच कॉफी की डालें। आपस में दोनों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद चेहरे पर लगा लें। 5 मिनट तक हल्के हाथों के दबाव से नाक पर स्क्रब करें। पानी और कॉटन की मदद से नाक आर लगे स्क्रब को साफ कर लें। इस तरह आप हफ्ते में 2 से 3 बार तक कॉफी से बनी स्क्रब चेहरे पर इस्तेमाल कर सकती हैं। पहली ही बार में आपको अपनी चेहरे की त्वचा में निखार नजर आने लगेगा। किसी भी नुस्खे को आजमाने से पहले आप एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

क्रॉप टॉप में फ्यूजन लुक क्रिएट करने ऐसे करें स्टाइल

अगर आप क्रॉप टॉप को एक फ्यूजन लुक में कैरी करना चाहती हैं तो ऐसे में आप खुद को कई अलग-अलग तरीकों से स्टाइल कर सकती हैं। गर्मी के मौसम में हम सभी क्रॉप टॉप को अपने स्टाइल का हिस्सा बनाते हैं और उसे अपने समर वार्डरोब में जगह देते हैं। हालांकि, यह देखने में आता है कि क्रॉप टॉप को अक्सर जीन्स या शॉर्ट्स के साथ ही स्टाइल किया जाता है। यह क्रॉप टॉप को स्टाइल करने का एक सिंपल तरीका है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार क्रॉप टॉप को वहीं सिंपल व बोरिंग तरीके से पहना जाए। अगर आप चाहें तो क्रॉप टॉप को बतौर फ्यूजन लुक भी कैरी किया जा सकता है। यह एक मॉडर्न स्टाइल है, जिसमें आप अपनी पसंद व फैशन च्वॉइस को ध्यान में रखकर थोड़ा वेस्टर्न व थोड़ा इंडियन मिलाकर कुछ हटकर स्टाइल बना सकती हैं। फ्यूजन स्टाइल में क्रॉप टॉप आपका लुक यकीनन बेहद ही डिफरेंट व स्टनिंग लगेगा। फ्यूजन लुक कैरी करने का एक फायदा यह भी होता है कि इसमें आप ढेरों एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हैं। इस तरह आप एक ही क्रॉप टॉप को कई अलग-अलग तरीकों से आसानी से स्टाइल कर पाते हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको क्रॉप टॉप को फ्यूजन लुक में कैरी करने के कुछ आसान तरीकों के बारे में बता रहे हैं-

क्रॉप टॉप के साथ पहनें धोती पैंट व स्टेटमेंट दुपट्टा

क्रॉप टॉप में फ्यूजन लुक क्रिएट करने के लिए उसके साथ धोती पैंट या स्टेटमेंट दुपट्टा कैरी किया जा सकता है। इसके लिए आप कोई सॉलिड कलर या प्रिंटेड क्रॉप टॉप लें। अगर आप किसी फंक्शन के लिए तैयार हो रही हैं तो ऐसे में सीक्वेंस या जरी वाला टॉप भी स्टाइल किया जा सकता है। इसके साथ आप बॉटम वियर में धोती पैंट्स या शरारा पैंट्स पहन सकती हैं। अगर टॉप स्टाइल ज्यादा लाउड है तो ऐसे में आप पैंट्स को वाइट, बेज या ब्लैक जैसे सिंपल कलर को चुनें।

इन तरीकों से आप सनबर्न की समस्या से पा सकती हैं राहत

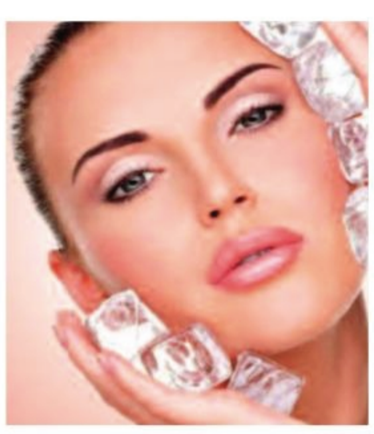

गर्मियों में घर से बाहर निकलते सनबर्न की समय हो सकती हैं। ऐसे में गर्मियों में बाहर निकलने से डर लगता है। अगर आप भी सनबर्न के कारण अपने जरूरी से जरूरी काम के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप इस गर्मी किन देसी तरीकों को अपनाकर आसानी से सनबर्न की समस्या से राहत पा सकती हैं।

एलोवेरा जेल जरूर लगाएं

सनबर्न से तुरंत राहत पाना है तो आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले आपको ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोना है। इसके बाद आप टिशू की मदद से अपने चेहरे को पोछें। फिर एलोवेरा जेल को पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद आप अपने चेहरे को धो सकती हैं। ध्यान रखें कि आपको फ्रेश एलोवेरा का ही अपने चेहरे पर इस्तेमाल करना चाहिए।

बर्फ लगाएं

सनबर्न अगर ज्यादा हो गया है तो आपको एलोवेरा के बाद अपने चेहरे पर बर्फ से सिकाई करना चाहिए। आईस क्यूब को साफ सूती कपड़ों के बीच में रखें। फिर इसे अपने चेहरे पर रगड़ें। ऐसे में आपका चेहरा चमकने लगेगा। अगर आपको ठंड ज्यादा लगती हैं तो आप आईस क्यूब को एक बड़ी कटोरी में डालें अब इसमें साफ पानी मिला लें। फिर इस पानी में आपको फेस को डुबोकर रखना है।

दो मिनट में मेकअप कर हो जाएं तैयार

पार्टी या फंक्शन में जाना हम सभी को पसंद होता है। लेकिन यहां पर जानें से पहले अपने लुक को सोचकर रखते हैं। ऐसा इसलिए ताकि हम तैयार होने में समय कम लगे। साथ ही जब हम तैयार हो जाएं तो सबसे अलग नजर आए।

कई सारे लोग रेडी होने के लिए पार्लर जाना भी पसंद करते हैं, ताकि मेकअप और हेयर स्टाइल क्रिएट करा सके। लेकिन हम आपको मेकअप आर्टिस्ट मीनाषी दत्ता ने जिन टिप्स को अपने वीडियो में बताया है उसके बारे में बताएंगे। इसमें उन्होंने 2 मिनट में मेकअप करने के तरीके को शेयर किया है। चलिए आपको भी बताते हैं कैसे आप 2 मिनट में मेकअप कर सकती हैं।

लगाए बीबी और सीसी क्रीम

अगर आपको बजट कम है तो ऐसे में आप बेस के लिए कंसीलर और फाउंडेशन की जगह बीबी और सीसी क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से खरीदें और चेहरे पर प्राइमर लगाने के बाद इसे अप्लाई करें। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे पूरे फेस पर ब्लेंड कर सकती हैं। इसके बाद पाउडर से इसे सेट करें।

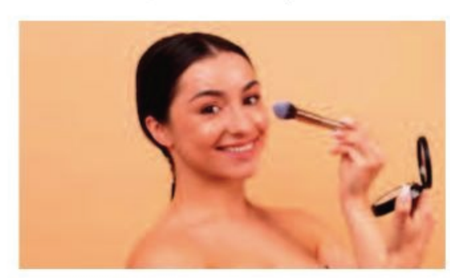

लिप टिंट का करें इस्तेमाल

कई लोग ब्लश लगाने के लिए पिंक कलर का ब्लश पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल यह कॉन्टोर के साथ भी आता है। लेकिन अगर आपके पास यह नहीं है तो इसकी जगह पर लिप टिंट का इस्तेमाल मेकअप के लिए कर सकती हैं। इसके आप गालों पर लगाएं और अच्छे से ब्लेंड करें। आप इसे लिप्स पर भी अप्लाई कर सकती हैं। इससे लिप्स हाइड्रेट रहेंगे। साथ ही आपको अलग से लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

क्रीमी आईशैडो का करें इस्तेमाल

आप महंगे पैलेट खरीदने की बजाए बाजार से जाकर क्रीमी आईशैडो को खरीद सकती हैं। यह हर मेकअप लुक के साथ जाता है ।

कार्नर न्यूज

फेडिंग के साथ बियर्ड का लुक थोड़ा और आ जाता है नुचुरल

आसानी से पा सकते हैं कूल फेडेड बियर्ड लुक महफिल में लोगों की नजरें नहीं हटेंगी आप से

-आजकल फैशन बियर्ड का ही है। अपने चेहरे के हिसाब से सभी पुरुष अलग-अलग तरह की बियर्ड रखते हैं। कभी विराट कोहली वाली तो कभी विक्की कौशल का स्टाइल पुरुषों को भा जाता है। इन्हीं लुक में से एक है बियर्ड फेडिंग। फेडिंग के साथ बियर्ड का लुक थोड़ा और नेचुरल आ जाता है।

दाढ़ी को कैसे परफेक्टली फेड करें

जिन पुरुषों ने अभी तक बियर्ड फेडिंग नहीं कराई है, उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप इस ट्रिक को आसानी से समझा जा सकता है।

सबसे पहले सफाई

बियर्ड फेडिंग शुरू करने से पहले बालों को धोकर बियर्ड कॉम्ब से सुलझा भी लें। ताकि फेडिंग करते हुए कोई दिक्कत न आए। सुलझाते हुए कॉम्ब नीचे की ओर चलाएं। बालों के ग्रोथ पैटर्न को फॉलो भी किया जा सकता है। अगर आप कंधा ऊपर की ओर चलाएंगे तो दाढ़ी के बाल ऊपर उठ जाएंगे। फेडिंग करते हुए ये उठे हुए बाल परेशानी बन सकते हैं। दरअसल बाल उठे हुए होंगे तो इनकी लेंथ बराबर से पता नहीं चलेगी। इसलिए नीचे की ओर कंघा करने के बाद दाढ़ी को बराबर से काट लीजिए। इस वक्त दाढ़ी जिस दिशा में उग रही है उसके उल्ट ऊपर की ओर हाथ चलाते हुए बियर्ड काटें। इस तरह से दाढ़ी की लम्बाई बराबर से आ सकेगी।

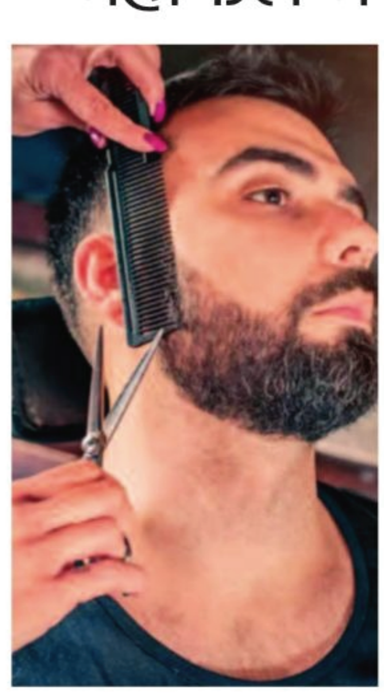

अब बनानी हैं लाइन

बियर्ड को बराबर से काटने के बाद अब बारी है कि लाइन बनाई जाएं। जिसमें गर्दन और गलों की लाइन शामिल है। आपको करना ये है कि ये लाइन बराबर से और परफेक्ट होनी चाहिए। इसकी शुरुआत गर्दन की ओर से करें। इसके लिए चेहरा उठाकर रखें।

अब गर्दन के बीच से एडम के ठीक ऊपर तक जाएं। इस वक्त आपको गर्दन के बीच से कान तक जोड़ने वाली लाइन भी बनानी होगी। अब गालों से मुंह के कोनों पर आएं और नेचुरल चीकलाइन से साइडबर्न तक आएं। इन लाइन से किनारे शेविंग कर दें।

फेडिंग के लिए हो जाएं तैयार

अब जब आपकी बियर्ड ट्रिम हो चुकी है और लाइन भी बन चुकी हैं तो आप फेड के लिए तैयार हैं। इस वक्त आपको फेडिंग ऊपर से नीचे की ओर करनी है।

गर्दन पर फेडिंग

गर्दन पर फेडिंग करके आपको और नेचुरल लुक मिल जाता है।इससे बियर्ड देखने में ज्यादा स्मूथ लगती है। इस दौरान आपको अपनी चिन उठाकर ही रखनी है।

बियर्ड के साइड

फेडिंग करते हुए बियर्ड के साइड पर भी काम करना होगा। इसमें कान के बीच से होते हुए ऊपर की ओर जाएं। हमेशा बाल उगने की उलटी दिशा में कटिंग करें।

जब साइडबर्न हो जाएं

जब साइडबर्न पर काम हो जाए तो चेहरे को यंग दिखाने के लिए, फेड को कानों के नीचे ले जाएं। इसके बाद चेहरा पतला दिखाना है तो आपको बियर्ड के किनारे टाइट रखने होंगे। इसका वोल्यूम जॉलाइन की ओर ही होना।

प्लास्टिक को लेकर चौपाटी के छोटे दुकानदारों पर हुई जुर्माने की कार्रवाई

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। नगर पालिका द्वारा प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर चौपाटी के छोटे दुकानदारों पर जुर्माने की कार्यवाही की है लेकिन इस कार्रवाई से छोटे दुकानदार इस बात से हैरान है कि जहाँ से उन्होंने उक्त प्लास्टिक खरीदा है वह दुकान भी इसी जगह है तो उस पर कार्यवाही क्यों नही हुई..? क्या नगर पालिका की कार्रवाई केवल चौपाटी में रोजी-रोटी कमाने वाले छोटे दुकानदारों तक ही सीमित है, जबकि शहर के कई बड़े प्रतिष्ठानों में खुलेआम प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। रविवार को नगर पालिका की टीम ने चौपाटी क्षेत्र में पहुंचकर प्लास्टिक एवं डिस्पोजल सामग्री का उपयोग करने वाले कई दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। व्यापारियों के अनुसार किसी पर 100 तो किसी पर 500 तक का जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने नगर पालिका कर्मचारियों का ध्यान चौपाटी के सामने स्थित बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों की ओर भी दिलाया, जहां कथित रूप से प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। चौपाटी के व्यापारियों का कहना है कि वे प्रतिदिन मेहनत कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। यदि शासन द्वारा प्लास्टिक प्रतिबंध लागू किया गया है तो उसका पालन सभी व्यापारियों के लिए समान रूप से कराया जाना चाहिए। केवल छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई करना और बड़े व्यापारियों को नजरअंदाज करना निष्पक्ष व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।व्यापारियों ने यह भी कहा कि नगर पालिका को चौपाटी की साफ-सफाई, अव्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं में सुधार पर भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि चौपाटी की समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं, लेकिन उनके समाधान के बजाय छोटे दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है।चौपाटी के दुकानदारों ने मांग की है कि प्लास्टिक प्रतिबंध के नियमों का पालन पूरे शहर में बिना किसी भेदभाव के कराया जाए, ताकि सभी व्यापारियों के साथ समान व्यवहार हो और कार्रवाई पारदर्शी दिखाई दे।

कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में रैली व प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ती अनियमितताओं, पेपर लीक की घटनाओं तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सोमवार को छात्र-युवा संगठनों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने

कलेक्टर को ज्ञापन

महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है।

इस अवसर पर अग्रसेन चौक (पुराना बस स्टैंड) से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-युवा एवं नागरिक शामिल हुए। शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित प्रदर्शन में युवाओं ने तख्तियां एवं महापुरुषों के चित्र लेकर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोशल एक्टिविस्ट एवं पर्यावरण प्रेमी बीपीएस पोया, जिला अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग, सूरजपुर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हृश्वश्वञ्ज, त्नष्ट-हृश्वञ्ज, स्स्ष्ट, ष्ट्क्रस्श्व जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं एवं पेपर लीक की घटनाओं से

लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में ष्ट्नक्क्स्ष्ट, व्यापम, शिक्षक भर्ती सहित विभिन्न चयन प्रक्रियाओं में उठे सवालों ने युवाओं के बीच विश्वास का गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए यहां के युवा भी शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य युवाओं के भविष्य की सुरक्षा एवं परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करना है।ज्ञापन में परीक्षा प्रणाली को पूर्णतः पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने, पेपर लीक में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, सभी अनियमितताओं की स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच तथा प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की गई। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग, आदिवासी युवा छात्र संगठन एवं अन्य संगठनों के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में छात्र-युवा एवं नागरिक उपस्थित रहे।सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग से शिव प्रताप सिंह आयाम ब्लॉक अध्यक्ष, सूरजपुर, गुलाब सिंह नेताम, विनय पावले अंजली सिंह आयाम प्रतापपुर, महेश सोनपाकर भैयाथान, लाकेश्वर मरावी (ब्लॉक अध्यक्ष, भैयाथान), प्रमोद सिंह मरावी कार्यकारिणी अध्यक्ष, रामानुजनगर एवं योगेश सिंह टेकाम शामिल रहे।

आदिवासी युवा छात्र संगठन से अशोक पैकरा प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़, आनंद मरकाम, कृष्णनारायण प्रताप चेरवा एवं दिनेश सिंह उर्रे, सामाजिक कार्यकर्ताओं में राजा सिंह टेकाम सहित नेहा सिंह, संदीप कुशवाहा, संतलाल उर्रे, अजय पावले, शिवम पैकरा, प्रदीप पैकरा, सुनील मरावी, सुमित पैकरा, अनुराग रक्सेल, दीपक धुर्वे, राजू चेरवा, पंकज सिंह, राकेश साहू, दीक्षित सिंह, माधुरी मरकाम एवं दुर्गा प्रसाद मरकाम, मंजू सिंह टेकाम,कवि राजवाड़े, रितांजली आयाम, उमेश साहू उपस्थित रहे।

एसपी की अपील : सुरक्षा को मजबूत करने अवैध प्रवासियों की सूचना देकर बने जिम्मेदार नागरिक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने को लेकर नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर जिले के थाना-चौकी की पुलिस के द्वारा अवैध प्रवासियों की सघनता से चेकिंग की जा रही है। अवैध प्रवासी चेकिंग अभियान के तहत पुलिस टीमों के द्वारा जनजागरूकता फ्लेक्स नागरिकों को प्रदाय कर अपील की जा रही है कि यदि उनके आसपास किसी संदिग्ध अथवा अवैध रूप से निवास कर रहे प्रवासी की जानकारी हो तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने नागरिकों से अपील किया है कि अवैध प्रवासियों की सूचना देकर जिम्मेदार नागरिक बनें, आपकी एक सूचना सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी। समय पर प्राप्त सूचना से कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

नागरिक अपने नजदीकी थाना अथवा टोल फ्री नंबर 1800-233-1905 पर संपर्क कर जानकारी साझा कर सकते हैं। यह भी अपील की गई कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें, केवल सत्यापित जानकारी ही पुलिस को दें तथा सुरक्षित, संगठित और जागरूक समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।

4 लाख रुपये कीमत का गांजा जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देशन में सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को अवैध कारोबार तथा मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।इसी क्रम में दिनांक 19.07.2026 को थाना प्रतापपुर पुलिस द्वारा ग्राम गोटगवां में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान अम्बिकापुर की ओर से बिना नंबर प्लेट की प्लेटिना मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर वाहन की डिक्की एवं उसके बैग की तलाशी ली, जिसमें 8 किलो 305 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजा की अनुमानित बाजार कीमत करीब 4 लाख रुपये आंकी गई है।पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम रमेशचन्द्र पिता राजाराम निषाद, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम राघौपुर, थाना कमासिन ब्लाक, जिला बांदा (उत्तरप्रदेश) बताया। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह उक्त गांजा उड़ीसा से लेकर उत्तरप्रदेश ले जा रहा था।पुलिस ने मौके से बरामद 8 किलो 305 ग्राम गांजा एवं परिवहन में प्रयुक्त प्लेटिना मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपी के

विरुद्ध धारा 20(बी) एवं 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे विधिवत गिरफ्तार किया है। प्रकरण में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश एवं पतासाजी की जा रही है।इस कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रतापपुर निरीक्षक नरेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक विवेक खलखो, पीएसआई सम्पत मरावी, विकास गजेन्द्र, प्रधान आरक्षक अलबिनुस तिर्की, विनोद परीड़ा तथा आरक्षक नौशाद, प्रकाश साहू एवं राजेश तिवारी की महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका रही।

पंचायत का सख्त फैसला, पेड़ काटने पर 5 हजार जुर्माना और सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले की ग्राम पंचायत करंजी में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

सोमवार को ग्राम पंचायत भवन में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में एक पंचनामा तैयार किया गया। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने शिकायत की है कि पंचायत क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमि पर लगे पेड़-पौधों की कुछ लोगों द्वारा अवैध कटाई की जा रही है। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि कोई व्यक्ति शासकीय भूमि पर लगे पेड़ों की कटाई करते हुए पाया जाता है,या बकरी के चारा के लिए डंगाल की कटाई की तो उस पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, पंचायत ने अवैध पेड़ कटाई की सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 हजार का इनाम देने का भी निर्णय लिया है। पंचायत का मानना है कि इससे ग्रामीणों की सहभागिता बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। यह निर्णय ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव तथा ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों के हस्ताक्षर के साथ पंचनामा तैयार कर लागू किया गया है। पंचायत के इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल माना जा रहा है।

कलेक्टर की सराहनीय पहल का संयुक्त शिक्षक संघ ने किया स्वागत

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। कलेक्टर के निर्देशानुसार विद्यालयों में बैगलेस डे के अवसर पर शिक्षक, विद्यार्थियों एवं पालकों की सहभागिता से शाला परिसर में स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाने के आदेश का संयुक्त शिक्षक संघ ने स्वागत किया है।संघ ने कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व की सीख देने का भी माध्यम हैं। ऐसे में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों की संयुक्त भागीदारी से विद्यालय परिसर की स्वच्छता, पौधों की देखभाल, अनुपयोगी सामग्री का निष्पादन तथा स्वच्छ वातावरण के निर्माण जैसे कार्य निश्चित रूप से बच्चों में श्रमदान, अनुशासन, स्वच्छता एवं सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करेंगे।दरअसल जिले के अनेक प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल में भृत्य की अनुपलब्धता के

कारण विद्यालय में साफ सफाई का संकट गहराते जा रहा था, विद्यालय में गंदगी पाए जाने पर उच्च अधिकारी संस्था प्रमुख पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते और बच्चों के सहयोग से साफ सफाई कराने का फोटो वायरल होने पर भी शिक्षकों पर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित होती। इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु संयुक्त शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी ने पिछली परामर्शदात्री समिति की बैठक में कलेक्टर से आग्रह किया था।कुछ दिनों पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी जी ने भी बच्चों के श्रमदान के माध्यम से शाला प्रांगण की साफ सफाई में सहयोग लेने की सीख देते हुवे पुरातन गुरुकुल व्यवस्था का स्मरण कराया था ।

संयुक्त शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार सिंह प्रतापपुर, कृष्णा सोनी सूरजपुर, पुष्पराज पाण्डेय प्रेमनगर,मोहम्मद महमूद, प्रमोद पाठक ओड़गी, कुलदीप सिंह भैयाथान, राधेश्याम साहू रामानुजनगर, ने कहा कि यदि इस प्रकार के कार्यक्रम शिक्षकों पर अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ डाले बिना, पर्याप्त संसाधनों एवं जनसहभागिता के साथ सदैव आयोजित किए जाएं तो यह शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता का भी उत्कृष्ट उदाहरण बनेंगे। संघ ने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से विद्यालयों का वातावरण और अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं प्रेरणादायी बनेगा, अब भयमुक्त होकर शिक्षक, छात्र छात्राओ के सहयोग से विद्या के मंदिर को और अधिक स्वच्छ रख सकेंगे।संघ ने जिले के कलेक्टर द्वारा शिक्षा एवं स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालयों को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए समाज, पालकों और शिक्षकों का सामूहिक प्रयास अत्यंत आवश्यक है।

कलेक्टर तक पहुँचा पतरापाली का पटेल नियुक्ति विवाद, मनमानी का आरोप

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। रामानुजनगर ब्लॉक के ग्राम पतरापाली का पटेल नियुक्ति विवाद अब कलेक्टर तक आ पहुँचा है।आज एक अभ्यर्थी ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए अभ्यर्थी घोषित करने की मांग की है।ग्राम पतरापाली में पटेल की नियुक्ति

कलेक्टर से न्याय की फरियाद

पिछले चार वर्ष से लंबित है।कहा जाता है कि राजनीति खींचतान के कारण यह नियुक्ति लंबित है।सियासी दबाव में बगैर किसी ठोस कारण के अभ्यर्थी का नामांकन रद्द करने का भी आरोप लग रहा है।इसी मसले को लेकर सोमवार को पटेल पद के अभ्यर्थी धनीराम यादव आज कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुँचे थे।धनीराम ने दिए शिकायत में कहा है कि यहां पटेल पद पर नियुक्ति विगत 4 वर्षों से अर्थात् सन् 2022 से चयन प्रक्रिया लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तहसीलदार रामानुजनगर राजनितिक प्रभाव मे आकर मनमानी कार्यवाही करना चाहते है जिससे 4 वर्षों से यह प्रक्रिया पूर्ण नही हो पा रही है। गत वर्ष सन् 2025 मे तहसीलदार रामानुजनगर ने ग्राम पंचायत पतरापाली के

पटेल पद के चुनाव हेतु 16.06.2025 की तिथि नियत की थी उस समय चारो उम्मीदवारों को पात्र घोषित किया गया था किन्तु बाद में राजनीतिक दबाव मे बिना किसी कारण के चुनाव मनमाने तरीके से स्थगित कर दिया था।

2026 मे चुनाव होना है किन्तु तहसीलदार अब पुनः राजनैतिक दबाव मे आवेदक की उम्मीदवारी इस आधार पर निरस्त कर दिया कि आवेदक का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है जबकि इस संबंध मे तहसीलदार ने गत वर्ष जांच करवाई थी जिसमे हल्का पटवारी ने दिनांक 18.08.2025 को अपना जांच प्रतिवेदन एवं पंचनामा प्रस्तुत कर बताया था की जांच मे आवेदक का अतिक्रमण नही पाया गया है, बल्कि अतिक्रमण आवेदक के भाई रामेश्वर का पाया गया है और इसी आधार पर आवेदक को योग्य उम्मीदवार पाते हुये दिनांक 16.06.2025 कों होने वाले चुनाव मे आवेदक को ही अभ्यर्थी घोषित किया गया था। बाद में फिर मनरेगा की राशि आवेदक द्वारा डबरी निर्माण करने का आरोप लगाया है, जो पूर्णतः गलत है आवेदक ने मनरेगा की राशि से कोर्ड डबरी का निर्माण किया है और न ही तहसीलदार ने कोई जांच की है मात्र मौखिक आरोप के आधार पर आवेदक की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है। धनीराम ने कलेक्टर से शिकायत पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पटेल पद पर उम्मीदवार घोषित किये जाने की मांग की है।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)
रा०प्र०क्र० / ब-121 / 2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संजय अग्रवाल आ० जगरनाथ अग्रवाल निवासी स्कूल रोड अम्बिकापुर थाना तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा पंजीकृत मुख्तार आम अनिल अग्रवाल आ० ईश्वरचन्द्र अग्रवाल निवासी एम.जी. रोड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की व्यपवर्तित भूमि ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 2/676 रकबा 0.020 हे0 भूमि को अनावेदक अनिमा केडिया पति सचिन केडिया निवासी कंपनी बाजार अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास निजी कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अंकन राशि 10,00,000/- मे सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुंजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 10/08/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांक 17/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

तहसीलदार
अम्बिकापुर सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)
रा०प्र०क्र० / ब-121 / 2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शफी अहमद खान आ० अब्दुल वहीद खान निवासी मकान नंबर 72 वार्ड क्रमांक 42 मोमिनपुरा अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की व्यपवर्तित भूमि ग्राम अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 2540/5 रकबा 0.394 हे0 मे से रकबा 0.026 हे0 भूमि को अनावेदक उषा गर्ग पति राजेश गर्ग निवास अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के पास दान करने की निजी कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अंकन राशि 13,50,000/- मे सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुंजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 10.08. 2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांक 17/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर सरगुजा

पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल के सामने अधूरी सड़क, गिट्टी पर चलने को मजबूर स्कूली बच्चे

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। ब्लॉक मुख्यालय रामानुजनगर में स्थित एकमात्र खेल मैदान इन दिनों अव्यवस्था का शिकार है। खेल मैदान के एक ओर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और दूसरी ओर पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्थित है। इसी खेल मैदान के किनारे बनाई जा रही सड़क का काम अधूरा छोड़ दिए जाने से स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।जानकारी के अनुसार खेल मैदान के किनारे बनाई गई सड़क के कुछ हिस्से में डामरीकरण का कार्य पूरा कर दिया गया है,

जबकि पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के सामने लगभग 80 से 100 मीटर सड़क पर केवल गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। स्कूल के ठीक सामने सड़क की यह स्थिति बच्चों के लिए परेशानी और दुर्घटना का कारण बन सकती है।स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सड़क के अधिकांश हिस्से में डामरीकरण किया जा सकता है, तो स्कूल के सामने सड़क को अधूरा क्यों छोड़ा गया है? जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि स्कूल के सामने डामरीकरण करने से बच्चों को परेशानी होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि डामरीकरण से बच्चों को परेशानी होगी, तो क्या सड़क पर बिखरी गिट्टी से बच्चों को परेशानी नहीं होगी?स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल के नवीन भवन निर्माण के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही के कारण खेल मैदान का समतलीकरण भी प्रभावित हुआ है। मैदान में समतलीकरण की आवश्यकता है, लेकिन इस ओर भी अब तक गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया है।इसके अलावा पूरे खेल परिसर में एक भी पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं है। शाम के समय खेल मैदान में अंधेरा छा जाता है, जिससे खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लॉक मुख्यालय के महत्वपूर्ण शैक्षणिक और खेल परिसर की इन मूलभूत समस्याओं की ओर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है।स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल के सामने अधूरी सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराया जाए, खेल मैदान का समतलीकरण कराया जाए और पूरे परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चों और खिलाड़ियों को सुरक्षित एवं बेहतर सुविधाएं मिल सकें।अब सवाल यह है कि बच्चों की सुरक्षा के नाम पर डामरीकरण रोकना जायज है, तो फिर स्कूल के सामने गिट्टी डालकर सड़क को अधूरा छोड़ना किस तरह उचित है?

फर्जी आधार कार्ड बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत होकर आरोपियों की जमानत कराने वाला आरोपी गिरफ्तार

कई न्यायालयों में कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ करने का मामला उजागर

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। पुलिस ने न्यायालय में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोपियों की जमानत कराने के गंभीर मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी देव प्रताप सिंह (34 वर्ष), निवासी ग्राम अजबनगर (रंगपारा) को अपराध क्रमांक 525/2026 में

गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319 एवं 337 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।मामले की विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने अपने पिता के नाम से कूटरचित (फर्जी) आधार कार्ड तैयार कराया और स्वयं को अपने पिता बताकर न्यायालय में उपस्थित हुआ। इसके बाद उसने अपने पिता के स्थान पर हस्ताक्षर कर आरोपियों की जमानत कराई। यह कृत्य न्यायालय को धोखे में रखकर किया गया, जिसे गंभीर आपराधिक कृत्य माना गया।जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित आरोपी के विरुद्ध पूर्व से भी ऐसे मामलों की जांच चल रही है। आरोपी द्वारा सूरजपुर न्यायालय के अपराधिक प्रकरण क्रमांक 28/2025 एवं 30/2025 में भी कथित रूप से कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर अन्य आरोपियों की जमानत कराई गई थी। इसके अतिरिक्त अंबिकापुर स्थित न्यायालय में भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक अन्य आरोपी की जमानत कराने का मामला जांचाधीन बताया गया है।

पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को धारा 35(ए) BNSS के तहत नोटिस देकर जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया था, लेकिन आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया। साथ ही फर्जी आधार कार्ड कहां तैयार कराया गया और उसे कहां रखा गया, इसकी भी स्पष्ट जानकारी नहीं दिया।

अत्याधुनिक 'अम्बिका डायग्नोस्टिक क्लिनिक' का शुभारंभ

अब अंबिकापुर में ही होगी बिना वायर-कैथेटर वाली हृदय जांच, 24 घंटे सेवा शुरू

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा संभाग के लोगों को अब इलाज के लिए रायपुर-बिलासपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अंबिकापुर में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस 'अम्बिका सोनोग्राफी डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशन क्लिनिक' का सोमवार को भव्य शुभारंभ दर्रीपारा स्थित सीएमएचओ कार्यालय के समीप हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. श्याम बिहारी जायसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया, जबकि प्रदेश के मंत्री राजेश अग्रवाल ने फीता काटकर क्लिनिक का विधिवत शुभारंभ किया।

इस मौके पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह संस्थान सरगुजा के लिए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। क्लिनिक में ऐसी हाईटेक तकनीक लगाई गई है जिससे बिना किसी वायर या कैथेटर डाले हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज की जांच की जा सकेगी। उन्होंने कहा, अब तक यह सुविधा प्रदेश के चुनिंदा बड़े अस्पतालों में ही थी। अब स्थानीय स्तर पर कम समय में सटीक जांच होने से मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा। अब क्षेत्र के मरीजों को अत्याधुनिक हृदय जांच के लिए रायपुर, बिलासपुर या अन्य बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। आधुनिक तकनीक से लैस इस संस्थान में कम समय में सटीक जांच की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा। उन्होंने इस पहल को क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव, युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, नपानि की महापौर मंजूषा भगत, नगर निगम के सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने भी अपने संबोधन में इस नई स्वास्थ्य सुविधा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होना क्षेत्र के नागरिकों के लिए राहत की बात है और इससे गंभीर मरीजों को समय पर बेहतर उपचार मिल सकेगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्याम लाल जायसवाल ने कहा कि, दामाद डॉ. तुषार आनंद ने पटना एम्स तथा नई दिल्ली के प्रतिष्ठित सर गंगाराम अस्पताल जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। इनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ अब सरगुजांचल के मरीजों को मिलेगा। उन्होंने क्लिनिक के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि यह संस्थान गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का नया केंद्र बनेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने वर्चुअली दिया उद्बोधन, मंत्री राजेश अग्रवाल ने काटा फीता

क्लिनिक के संचालक परमानंद तिवारी ने बताया कि, संस्थान में उच्च गुणवत्ता की जांच सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सहित अन्य राज्यों से अनुभवी विशेषज्ञों की टीम को जोड़ा गया है। मरीजों को विश्वसनीय एवं त्वरित जांच सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी आधुनिक उपकरण स्थापित किए गए हैं। नई सुविधा के शुरू होने से अब अंबिकापुर सहित पूरे सरगुजा संभाग के मरीजों को बेहतर, त्वरित और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी। उन्होंने बताया कि,क्लिनिक का संचालन डॉ. तुषार आनंद, डॉ. अनीशा जायसवाल, शिवलाल जायसवाल एवं स्वयं उनके द्वारा किया जाएगा।

24 घंटे मिलेंगी ये सुविधाएं

संस्थान में अत्याधुनिक सीटी स्कैन, सोनोग्राफी (अल्ट्रासाउंड), डिजिटल एक्स-रे, मैमोग्राफी सहित विभिन्न आधुनिक डायग्नोस्टिक एवं इंटरवेंशनल चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ ही 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में भी मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके। शुभारंभ समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने संस्थान का अवलोकन कर उपलब्ध अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की जानकारी ली तथा इसे सरगुजा संभाग की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

छात्रावासों में घोटाले का जिन्न, निरीक्षण में खुली अव्यवस्थाओं की पोल

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। जिले के आदिवासी छात्रावासों में बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर के नेतृत्व में जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित एवं जिले के अंतिम सीमा में स्थित ग्राम कोगवार एवं बलंगी छात्रावासों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सामने आई अव्यवस्थाओं ने समाज प्रतिनिधियों को चौंका दिया। इनका कहना है कि बच्चों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है, जिससे आदिवासी विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

समाज की टीम के अनुसार, कोगवार छात्रावास में निरीक्षण के दौरान केवल 15 बच्चे ही मौजूद मिले, जबकि उपस्थिति पंजी में करीब 50 विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज थी। वहीं बच्चों के लिए खाने के चावल में बड़े-बड़े कंकड़, बच्चों को लगाने के दिया गया तेल एक्सपायरी पाया गया। खाने का तेल उपलब्ध नहीं था। स्वास्थ्य परीक्षण रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर तक संधारण नहीं किया गया था। छात्रावास अधीक्षिका के द्वारा आवश्यक दस्तावेज छात्रावास में उपलब्ध नहीं कराया गया, पूछने पर कहा कि पानी में भीग गया है इसलिए अपने घर में ले जाकर रखी हूं। अचंभित कर देने वाली बात यह है कि जब अधीक्षिका छात्रावास में रहती हैं तो रजिस्टर घर में कैसे? ऐसे में छात्रावास संचालन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बलंगी छात्रावास में भी कई खामियां मिलने का दावा किया गया है, वहां भी व्यवस्थाओं को लेकर संतोषजनक स्थिति नहीं मिली। छात्रावास कैंपस के अंदर का नल कई महीनों से खराब पड़ा है। वहीं बच्चों के सुरक्षा की दृष्टि से हॉस्टल के बाउंड्री के ऊपर सेफ्टी तार लगाना जरूरी है। भ्रमण के दौरान जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर ने कहा कि आदिवासी समाज के बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में लंबे समय से प्रभारी व्यवस्था के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर छात्रावासों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित आवासीय वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए, वे बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। बसंत कुजूर ने बताया, पूरे मामले की जानकारी जिला कलेक्टर को दी जाएगी और दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की जाएगी।

'मंथली कमीशन' के आरोप से बढ़ी हलचल

सूत्रों के हवाले से कथित मंथली कमीशन की चर्चा सामने आई। नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया गया कि जिले के कुछ छात्रावासों से हर महीने 10 से 20 हजार रुपये तक कमीशन के रूप में भेजे जाने की चर्चा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी अभी सामने नहीं आया है। यदि इन आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो यह आदिवासी विद्यार्थियों के अधिकारों और उनके विकास के लिए मिलने वाले सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का गंभीर मामला बनकर सामने आ सकता है।

अधीक्षक बनने के लिए लगती है बोली

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अधिकांश आश्रम एवं छात्रावास में नियम विरुद्ध अधीक्षक बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। विश्वस्त सूत्रो ने बताया कि बिना चढ़ावा के कोई आश्रम छात्रावास अधीक्षक नहीं बन सकता है, ऐसे में समझा जा सकता है कि आश्रम, छात्रावास भी कमाई का जरिया बनकर रह गया है। आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी बेपरवाह हैं। गरीब आदिवासी बच्चों के हक पर डाका डालकर अवैध कमाई के लिए इस विभाग में केवल प्रभारी-प्रभारी का खेल चल रहा है

पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव आज

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। समग्र शिक्षा (शिक्षा विभाग), जिला सरगुजा द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 अंतर्गत जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन 21 जुलाई को दोपहर 12 बजे से पी.जी. कॉलेज ऑडिटोरियम, अंबिकापुर में किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सांसद चिंतामणि महाराज करेंगे। विशिष्ट अतिथि विधायक लुण्ड्रा प्रबोध मिंज, विधायक सीतापुर रामकुमार टोप्पो, गृह निर्माण मंडल छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष राम किशुन सिंह, जिला पंचायत सरगुजा की अध्यक्ष निरूपा सिंह, महापौर मंजूषा भगत, जिला पंचायत सरगुजा के उपाध्यक्ष देवनारायण यादव तथा सभापति हरमिन्दर सिंह टिन्नी होंगे।

एमसीबी के सीएमएचओ पर गंभीर आरोप, रेडक्रॉस प्रतिनिधि ने की शिकायत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के प्रदेश प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता रामनरेश पटेल ने जिला एमसीबी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और लापरवाही के आरोप लगाते हुए राज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने जांच नहीं होने पर 18 अगस्त को रायपुर में धरना देने की चेतावनी भी दी है।

रामनरेश पटेल ने इस संबंध में सौंपे गए पत्र में बताया है कि एमसीबी जिला के रेडक्रॉस सोसायटी की गतिविधियों में सीएमएचओ कोई ध्यान नहीं देते। अगस्त 2024 में राज्यपाल द्वारा एमएमयू को हरी झंडी देने के बाद इसका संचालन 02.08.2025 से चेयरमैन शैलेष जैन द्वारा शुरू कराया गया क्योंकि डॉक्टर की नियुक्ति जुलाई 2025 के अंत में और स्टाफ नर्स की नियुक्ति सितंबर 2025 में हुई थी। आरोप है कि सीएमएचओ ने 21.05.2025 से 01.08.2025 तक फर्जी संचालन बताकर डीजल व अन्य सामानों का पैसा निकाल लिया। ये भी नहीं बताया कि किस डॉक्टर-नर्स से काम कराया गया क्योंकि एमएमयू चली ही नहीं थी। जून 2025 में बृजभूषण तिवारी को 15000 रुपये प्रतिमाह वेतन पर ऑपरेटर नियुक्त किया गया, जबकि वह न एमएमयू में काम करता है न रेडक्रॉस में। इस राशि की वसूली सीएमएचओ से करने की मांग की गई है। इन्होंने मनेंद्रगढ़ में संचालित एक ब्लड बैंक पर रक्त को महंगे दाम में बेचने और इसे सीएमएचओ का संरक्षण प्राप्त होने सहित अन्य कई गंभीर आरोप लगाये हैं।

स्वास्थ्य विभाग के आवास में अनियमितता

आरोप है कि, चैनपुर स्थित स्वास्थ्य विभाग की आवासीय कॉलोनी में अधिकांश अपात्र लोगों को आवास दे दिया गया है। उनसे मोटी रकम ली जाती है, जबकि रिक्त पदों के कर्मचारियों को आवास नहीं मिल रहा है। इससे शासन को आर्थिक क्षति हो रही है। रेडक्रॉस कार्यालय में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है, इस कारण कार्यालय कभी नहीं खुलता। रामनरेश पटेल ने राज्यपाल से मांग की है कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर सीएमएचओ के विरुद्ध एक माह के अंदर कार्रवाई करके उन्हें हटाया जाए। कार्रवाई नहीं होने पर 18 अगस्त को रेडक्रॉस भवन रायपुर के समक्ष धरना देने की चेतावनी दी गई है।

लक्ष्मणगढ़ के अवधेश साहू ने पास की एआईबीई परीक्षा, यू-ट्यूब से युवाओं को दे रहे उद्यमिता का पाठ

छ.ग.फ्रंटलाइन उदयपुर। विकासखंड के ग्राम लक्ष्मणगढ़ निवासी अवधेश साहू पिता सुखराम साहू ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, (एआईबीई) जून-2026 परीक्षा उत्तीर्ण कर अधिवक्ता की उपाधि प्राप्त की है। ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास करके इन्होंने क्षेत्र का नाम रोशन किया। अवधेश यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जिसके 30 हजार से अधिक सब्सक्राइबर और 44 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। वे नामचीन उद्यमियों के पॉडकास्ट के जरिए युवाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करते हैं। अवधेश ने कहा, न्याय, शिक्षा और उद्यमिता किसी भी सशक्त राष्ट्र की आधारशिला हैं। अधिवक्ता के रूप में संविधान के आदर्शों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। अवधेश साहू ने अपनी इस सफलता का

पूरा श्रेय अपने माता-पिता के त्याग, गुरुजनों के मार्गदर्शन, शुभचिंतकों के सहयोग और ईश्वर के आशीर्वाद को दिया है। इनकी उपलब्धि से क्षेत्रवासी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

संसाधनों की कमी को बनाया ताकत

ग्रामीण परिवेश से निकलकर देश की प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परीक्षा में सफलता प्राप्त किए अवधेश ने यह साबित कर दिया है कि यदि संकल्प दृढ़ हो और परिश्रम अनुशासित, तो सीमित संसाधन कभी भी बड़े सपनों की राह में रोड़ा नहीं बन सकता है। उनकी यह कामयाबी क्षेत्र के अन्य युवाओं को शिक्षा, कानून (विधि) और राष्ट्रसेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई राह दिखाएगी।

भाजपा महिला मोर्चा की कार्यसमिति बैठक में संगठन विस्तार और बूथ सशक्तिकरण पर जोर

छ.ग.फ्रंटलाइन भटगांव। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भटगांव मंडल की कार्यसमिति बैठक रविवार को आयोजित हुई। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण, आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रणनीति तथा जनसंपर्क अभियान को प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। महिला कार्यकर्ताओं से संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और घर-घर तक संगठन की विचारधारा पहुंचाने तथा बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नूतन विश्वास ने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से संगठन की गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। जिला पदाधिकारी ओंकार सिंह एवं भटगांव मंडल अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने संगठनात्मक विषयों पर मार्गदर्शन देते हुए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा से अवगत कराया। बैठक में जिला महामंत्री अशोक सिंह, जिला कोषाध्यक्ष राजू जायसवाल, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष पूनम तिवारी, वीरेंद्र गुप्ता, विजय राजवाड़े, महेंद्र सिंह मार्को, हीरा सिंह, महाराजिया सिंह सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। बैठक का समापन संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाने तथा आगामी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।

स्कूल मार्ग के विवाद में बच्चों को लेकर पहुंचे कलेक्टोरेट

पिकअप में लाए गए बच्चे, डीईओ ने कहा होगी कार्रवाई

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर से लगे सोनपुर कला के सरनापारा में निजी भूमि से गुजरने वाले स्कूल मार्ग को लेकर विवाद गहरा गया है। शुक्रवार को ग्रामीण प्राथमिक स्कूल के तीन दर्जन से अधिक बच्चों को असुरक्षित तरीके से पिकअप वाहन में बैठाकर कलेक्टोरेट पहुंच गए और रास्ता खुलवाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि, सरनापारा प्राथमिक स्कूल जाने का रास्ता निजी भूमि से होकर गुजरता है। भूमि स्वामी ने मार्ग बंद कर दिया है, जिससे बच्चों को स्कूल आने-जाने में दिक्कत हो रही है। इसी को लेकर वे बच्चों के साथ कलेक्टोरेट पहुंचे। इस दौरान शिक्षकों की भूमिका पर भी सवाल उठे। बताया गया कि शिक्षक बाइक, स्कूटी से आए, जबकि छोटे बच्चों को पिकअप में भरकर लाया गया। इससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है।

मुझे मिली है जानकारी-मामले में डीईओ दिनेश झा ने कहा, 'मुझे जानकारी मिली है, यह गलत है। बच्चों को जमीन विवाद में नहीं लाना चाहिए था। मामले की जांच कराकर शिक्षकों पर कार्रवाई करूंगा।'

रामनामी परंपरा की गाथा को राष्ट्रीय सम्मान, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का बढ़ा गौरव

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'राम-नामी' को 'सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म' का सम्मान प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ में हर्ष का वातावरण है। इस उपलब्धि को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और आध्यात्मिक धरोहर के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक भरतबाला गणपति एवं पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है।

संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने संदेश में कहा कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में डॉक्यूमेंट्री फिल्म राम-नामी को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का सम्मान प्राप्त होना छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल एक फिल्म की उपलब्धि नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है।

स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने सीएमएचओ पहुंचे अस्पताल

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह ने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति, अस्पतालों की व्यवस्थाओं तथा वर्षा ऋतु में फैलने वाली मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान डॉ. सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बगरा, 100 शैय्या सिविल अस्पताल वाड्रफनगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलंगी, उप स्वास्थ्य केंद्र कोगवार तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रघुनाथनगर का दौरा किया। उन्होंने ओपीडी, आईपीडी, प्रयोगशाला, फार्मेसी, एक्स-रे कक्ष, लेबर वार्ड, एनबीएसयू एवं एनआरसी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण में अस्पतालों की साफ-सफाई एवं मरीजों के भोजन की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। सीएमएचओ ने अस्पतालों में आवश्यक दवाओं के साथ एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) एवं एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा नवजात शिशु देखभाल इकाई को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाए रखने के निर्देश दिए। रघुनाथनगर एवं बलंगी में आयोजित सेक्टर बैठकों में उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए वर्षा ऋतु में मलेरिया, डेंगू एवं अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में जीवनरक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, समय पर उपचार एवं स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। डॉ. विजय कुमार सिंह ने कहा कि जिले के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने, स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता बनाए रखने तथा शासन की जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा

भालूमाड़ा जंगल में हाथी का हमला, पुटू बिनने गया वृद्ध गंभीर

वृद्ध का टूटा जबड़ा, पत्नी भी घायल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा इलाज

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र के भालूमाड़ा जंगल में सोमवार सुबह पुटू-खुखड़ी बीनने गए वृद्ध दंपती पर हाथी ने हमला कर दिया। हमले में 55 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सायर निवासी बिहानू उम्र 55 वर्ष अपनी पत्नी संपत के साथ सुबह करीब 7 बजे जंगल में पुटू बिनने गया था। इसी दौरान उनका सामना हाथी से हो गया। जान बचाकर भागते समय हाथी ने बिहानू का पीछा कर उस पर हमला कर दिया। हमले में उनका जबड़ा टूट गया और शरीर में गंभीर चोटें आईं। इधर घबराहट में भाग रही पत्नी संपत गिरकर घायल हो गई। ग्रामीणों की मदद से दोनों को उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बिहानू को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया है। पत्नी का इलाज उदयपुर में जारी है। इन दिनों पुटू-खुखड़ी की अच्छी कीमत के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण जंगल जा रहे हैं। वन विभाग ने हाथियों की सक्रियता वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतने और बिना जानकारी जंगल न जाने की अपील की है।

होली क्रॉस के 81 होनहारों ने रचा सफलता का नया कीर्तिमान

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सीबीएसई सत्र 2025-26 से कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षा का प्रावधान लागू किया गया है। इसका लाभ उठाकर होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों ने सफलता का नया कीर्तिमान रचा है। पहली बोर्ड परीक्षा में स्कूल के 78 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए थे। दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल 46 विद्यार्थियों में से 3 और छात्रों ने 90% से ऊपर स्कोर कर लिया। इसके बाद अब स्कूल के 81 विद्यार्थी 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले हो गए हैं। नई सूची में शामिल होने वाले छात्र समर जायसवाल 91.2%, सृष्टि सिन्हा 91% और नरगिस खातून ने 90.6% अंक लाकर स्कूल का गौरव बढ़ाया है। वहीं प्रथम परीक्षा में सर्वोच्च 98.4% लाने वाले पुष्कल सिंह के साथ अब अभिषेक सोनी ने भी 98.4% अंक प्राप्त कर टॉपर की बराबरी की है। विद्यालय की प्राचार्या डॉ. सि. जेस्सी थेक्कन ने सभी होनहार विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर